दैनिक समाचार पत्र

देश का दर्पण न्यूज

राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली व महाराष्ट्र से प्रकाशित

वर्ष-5, अंक:136 | जयपुर, शुक्रवार, 25 जुलाई 2025 | मूल्य : 5.00 | पेज:

अब आपके मोबाइल पर डिजिटिल अखबार

प्रदेश के ताजा समाचार

अपने लेख एवं समचार भेंजे

सम्पादक : उमेन्द्र राजपूत

7014997449, 9636058201

Email : deshkadarpannews@gmail.com

web.: www.deshkadarpannews.co

मंडी के सरकाघाट में दर्दनाक बस हादसा, पांच की मौत, 20 घायल

एजेंसी

मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस सरकाघाट के मसरेन के पास गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में बस में सवार 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे में 16 वर्षीय युवक सहित पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य महिलाएं की हालत भी नाजुक बनी हुई है। डीएसपी ने मौत की पुष्टि की है। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे मसरेन के त्रांगला गांव के पास एक मोड़ पर हुआ। बताया जा रहा है कि बस मोड़ से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत बचाव कार्य में जुट गए। सरकाघाट के डीएसपी भी मौके के लिए रवाना हो गए

हैं और उन्होंने हादसे की पुष्टि की है। त्रांगला गांव की एक महिला, मधु ने बताया कि उनके घर के पास ही यह हादसा हुआ है। फिलहाल, घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाने का काम चल रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार मोड़ पर नियंत्रण खोने से यह दुर्घटना हुई है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत व बचाव कार्य जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पोस्ट करते हुए कहा कि मंडी ज़िला के सरकाघाट उपमंडल के मसेरन के निकट तारंगला में एचआरटीसी बस के खाई में गिरने से पांच लोगों के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाने और उपचार दिलाने के लिए ज़िला प्रशासन को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। दुःख की इस घड़ी में, मैं दिवंगत जनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस हादसे को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा कि मंडी में हुआ बस हादसा बहुत ही दुखद है और मैं ईश्वर से सभी के लिए कुशता की प्रार्थना करता हूं.. प्रशासन से अनुरोध है कि घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था करें।

राज्यसभा के 6 सदस्य सेवानिवृत्त, उज्ज्वल निकम ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की

एजेंसी

नई दिल्ली। पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर गुरुवार को राज्यसभा में चौथे दिन भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा के छह सदस्यों को विदाई देने के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 02 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही उज्ज्वल निकम ने राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने मराठी में शपथ ली। उसके बाद आवश्यक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे गये। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन से सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई दी। एम मोहम्मद अब्दुल्ला (डीएमके), एन चंद्रशेखरन (एआईएडीएमके), अंबुमणि रामदास (पीएमके), एम शनमुगम (डीएमके), वाइको (एमडीएमके) और पी विल्सन (डीएमके) का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त

हुआ। पी विल्सन कल दोबारा सदन में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। इस दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने देश में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की। एमडीएमके नेता वाइको ने राज्यसभा में विदाई भाषण में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ईलम तमिलों की त्रासदी और नरसंहार के बारे में 13 बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

तेलंगाना में ओबीसी को 42 फीसदी आरक्षण की सिफारिश पर राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजारः खरगे

नई दिल्ली। तेलंगाना सरकार ने राज्य में हुए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर स्थानीय निकाय चुनावों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। इस फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अपने एक्स हैंडल से खुशी जाहिर की।उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने जिस वैज्ञानिक और व्यापक तरीके से सर्वेक्षण कराया है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है। इस आधार पर राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 42 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की है, जो अब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। उन्होंने इसे कांग्रेस पार्टी के सामाजिक न्याय, समानता और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए एक नए आंदोलन की शुरुआत बताया। खरगे ने लिखा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय की लड़ाई दशकों से हाशिए पर पड़े एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदायों को एक सशक्त आवाज दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा होने के बावजूद ये समुदाय न्यायपालिका, नौकरशाही, कॉर्पोरेट और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व से वंचित है। उन्होंने

उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में संसद में दिए एक उत्तर के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर पदों के लिए ओबीसी वर्ग के 80 फीसदी और एसटी वर्ग के 83 फीसदी पद रिक्त हैं। खरगे ने कहा कि देशभर में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को हटाया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कराए गए जाति सर्वेक्षण को जन दबाव में लिया गया फैसला बताया।

चुनाव बहिष्कार को लेकर सहयोगी दलों से करेंगे बातः तेजस्वी यादव

पटना । बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में किसी भी सही मतदाता का नाम नहीं काटे जाने के सरकार द्वारा दिए गए भरोसे के बाद भी इसके विरोध को लेकर विपक्ष के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि वोट की चोरी की पूरी तैयारी है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वोटों की चोरी तो हो ही रही है। उन्होंने कहा, ÷हमलोगों के पास पूरा विकल्प है कि जब बेईमानी ही करना है, चोरी ही करनी है, लोकतंत्र को समाप्त करना है, जनता का अधिकार छीनना है तो हमलोगों का चुनाव बहिष्कार का भी विकल्प खुला है। हमलोग जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं व महागठबंधन के घटक दलों से भी इसे लेकर बात करेंगे। उन्होंने चुनाव में हार के डर से भागने की बात पर कहा कि अगर हार से डरते तो क्या इतनी बार चुनाव लड़ते? चुनाव आयोग जब भाजपा का ही पार्ट बन गया, लाखों वोटरों का वोट काट दिया गया और सदन में खुलेआम झूठ बोला गया, तो क्या है? मृत लोगों के नाम काटे जाने को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह हमेशा होता है। पुनरीक्षण और गहन पुनरीक्षण को मिला दिया गया। गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ और पुनरीक्षण की अभी फरवरी में लिस्ट आई है। यह तो हर साल की प्रक्रिया है।एसआईआर में संदेह को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक अगस्त के बाद चुनाव आयोग असली खेल करने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों को पता है कि हमारा कौन सा बूथ मजबूत है और कौन सा कमजोर है, वैसे उन्हें भी पता होगा कि हमारा कौन सा बूथ मजबूत है और कौन सा कमजोर है। बताया गया कि बिहार मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का प्रथम चरण समाप्ति की ओर है। चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि वोटर लिस्ट से कोई योग्य मतदाता छूटने न पाए और कोई अयोग्य मतदाता जुड़ न जाए। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, एसआईआर में अब तक 98.01 प्रतिशत मतदाता कवर किए जा चुके हैं। 20 लाख मृतक मिले, जबकि 28 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम पाए गए।

सेवा में ही मेवा है : राष्ट्रपति ने स्काउट्स एवं गाइड्स को किया सम्मानित, 7 साल बाद पुनर्जीवित हुई परंपरा

एजेंसी

नई दिल्ली। 22 जुलाई 2025 का दिन भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण बन गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 उत्कृष्ट सदस्यों को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्रमाणपत्र प्रदान किए। यह समारोह 2015 के बाद पहली बार आयोजित किया गया, जिसने लगभग 7 साल से रुकी हुई इस सम्मान की परंपरा को पुनर्जीवित किया। ये पुरस्कार वर्ष 2018 से 2021 तक की अवधि के लिए उनके अद्वितीय समर्पण और सेवा के लिए दिए गए। समारोह की शुरुआत से पहले, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं और पदाधिकारियों को राष्ट्रपति भवन प्रोटोकॉल के अनुसार गोदावरी हॉल में लाया गया। इसके बाद, एक औपचारिक बैठक महानदी हॉल में हुई, जिसमें राष्ट्रपति को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का स्कार्फ पहनाया गया और आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दिया गया। पूर्वाह्न 11:10 बजे, राष्ट्रपति ने गोदावरी हॉल में प्रवेश किया, जहां उनका स्वागत सलामी के साथ किया गया। इसके बाद भावपूर्ण तरीके से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की प्रार्थना 'दया कर दान भक्ति का' प्रस्तुत की गई, जिसने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, बीएसजी के

अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार जैन ने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया और बताया कि सभी पुरस्कार विजेता स्काउट/गाइड वचन को जीवन में अपनाते हुए दूसरों की सेवा में सबसे आगे रहे हैं। मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के. के. खंडेलवाल ने संगठन के इतिहास और उसके उद्देश्यों की जानकारी देते हुए गर्व के साथ बताया कि बीएसजी अपनी प्रार्थना और वादे में समर्पण को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने वाला एकमात्र संगठन है। उन्होंने महात्मा गांधी के उस कथन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने हर घर में स्काउट्स एवं गाइड्स जैसे प्रशिक्षित बच्चों की कामना की थी। अपने प्रेरणादायक संबोधन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पाली, राजस्थान में जंबूरी में अपनी भागीदारी को अविस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने 50फीसदी पुरुषों और 50फीसदी महिलाओं की भागीदारी की सराहना की, और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स को अपनी सदस्यता एक करोड़ तक बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर देते हुए कहाः 'खुद के लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिएँ।' और 'सेवा में ही मेवा है', यह मूल्य स्काउट्स एवं गाइड्स में प्रतिदिन व्यवहार में लाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे समर्पित युवाओं के साथ भारत शीघ्र ही अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगा। समारोह के बाद, सभी सदस्यों को ब्रह्मपुत्र हॉल में जलपान के लिए आमंत्रित किया गया और राष्ट्रपति भवन के विभिन्न प्रतिष्ठित कक्षों जैसे अशोक हॉल, नर्मदा हॉल और गणतंत्र हॉल का निर्देशित भ्रमण कराया गया।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने या कटवाने के लिए अब भी एक माह का समयः चुनाव आयोग

एजेंसी

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त और 1 सितंबर के बीच राजनीतिक दल योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वा भी सकते हैं और अगर किसी का नाम गलती से जुड़ गया है तो उसे हटावा भी सकते हैं। चुनाव आयोग का यह वक्तव्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच आया है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के आदेश पृष्ठ 3, पैरा 7(5) के अनुसार, किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक एक महीने का समय मिलेगा ताकि वे किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करा सकें, जिन्हें बीएलओ/बीएलए ने छोड़ दिया हो। इसके साथ बीएलओ/बीएलए के गलत तरीके से शामिल किए गए

किसी भी मतदाता के नाम को कटवा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्ष लगातार अपना विरोध दर्ज कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया अल्पसंख्यक और पिछड़ों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने का तरीका है। विपक्ष के इसी विरोध के चलते पिछले दो दिन से संसद के दोनों सदनों में कोई कार्य नहीं हो पाया है।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में बंद पड़ी कंपनी में चल रही ड्रग की फैक्टरी में पुलिस का छापा, 88 करोड़ की ड्रग बरामद

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड औद्योगिक एस्टेट में बंद पड़ी कंपनी में चल रही ड्रग फैक्टरी में पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस ने यहां से 88 करोड़ 92 लाख रुपये मूल्य की 'केटामाइन' नामक प्रतिबंधित ड्रग जब्त की है। इस मामले में महाड एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की टीम ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार महाड औद्योगिक एस्टेट में प्लॉट नंबर ई 26/3 में रोहन केमिकल्स नामक कंपनी कई महीनों से बंद थी। लेकिन इसी बंद कंपनी में बड़े पैमाने पर ड्रग का निर्माण किया जा रहा था। इसके बारे में रायगढ़ ग्रामीण पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी। इसके आधार पर रायगढ़ ग्रामीण पुलिस और एमआईडीसी ने बीती रात रोहन केमिकल्स नामक कंपनी पर छापा मारा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 'केटामाइन' नामक प्रतिबंधित पदार्थ बड़े पैमाने पर मिला। इसके

बाद पुलिस ने सभी ड्रग जब्त कर लिया और चार लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 1985 के तहत गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों की पहचान मच्छिंद्र भोसले, सुशांत संतोष पाटिल, शुभम सुतार और रोहन गवास के रुप में की गई है। महाड एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है और ये पदार्थ कैसे बेचे गए। इन चारों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 8(सी), 22(सी), 25, 27(ए), 29, 42 और बी.एन.एस. 2023 की धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गहन छानबीन जारी है।

उद्योगपति अनिल अंबानी के मुंबई स्थित कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

एजेंसी

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को सुबह से उद्योगपति अनिल अंबानी की मुंबई स्थित कंपनियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर-निदेशक अनिल डी अंबानी को %धोखाधड़ी% के रूप में वर्गीकृत करने के कुछ ही दिनों बाद की जा रही है। ईडी की टीम को छापेमारी के दौरान इससे जुड़े कई सबूत मिले हैं, लेकिन ईडी की टीम ने छापेमारी से संबंधित कोई अधिकृत ब्योरा नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार ईडी की यह कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दो

प्राथमिकी सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। इसी जानकारी के आधार पर आज सुबह ईडी की टीम मुंबई स्थित अनिल अंबानी के कार्यालयों और संस्थानों पर पहुंची थी और अब तक छापेमारी जारी है। व्यापक जांच के तहत अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों की भी तलाशी ली जा रही है।

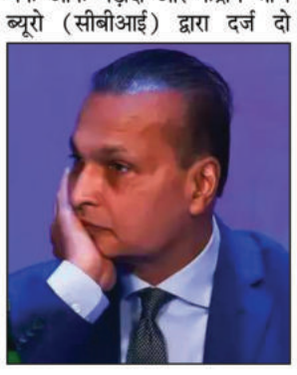

ईडी का दावा है कि उसने सार्वजनिक धन को दूसरी जगह भेजने की एक सुनियोजित योजना के सबूत उजागर किए हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई बताया जा रहा है कि यह जांच 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपये के ऋणों के संदिग्ध अवैध डायवर्जन पर केंद्रित है। ईडी अधिकारियों के अनुसार समूह की कंपनियों को ऋण वितरित किए जाने से कुछ समय पहले ही बैंक के प्रवर्तकों से जुड़ी संस्थाओं को धनराशि हस्तांतरित कर दी गई थी। अधिकारियों ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से संबंधित निष्कर्ष ईडी के साथ साझा किए हैं। ईडी के मुताबिक कॉर्पोरेट ऋण वितरण में अचानक वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गई। इस मामले में यस बैंक के पूर्व प्रमोटरों से जुड़े रिश्वतखोरी के पहलू की भी जांच की जा रही है।

'हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे' राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी दी

एजेंसी

नई दिल्ली । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की टिप्पणियों को बकवास बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी इससे बच नहीं सकते क्योंकि ÷हम उनके पास आएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह बयान तेजस्वी यादव की चुनाव बहिष्कार वाली टिप्पणी पर किए गए सवाल पर दिया। उन्होंने एसआईआर मुद्दे पर दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, ÷यह बहुत गंभीर मामला है। चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग की तरह काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कुछ बयान दिया है, यह पूरी तरह से बकवास है। सच तो यह है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर कर्नाटक का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग ने गड़बड़ी करने दी, जिसके 90 प्रतिशत नहीं, बल्कि 100 प्रतिशत सबूत ठोस हैं। अभी एक निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद गड़बड़ी का पता चला। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश ने खनन क्षेत्र में अर्जित की ऐतिहासिक उपलब्धि

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में खान विभाग ने मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान पूरे देश में मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में पहले पायदान पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में अधिसूचित किए गए प्रावधानों से अब तक पूरे देश में प्रधान खनिज के 500 ब्लॉक आवंटित हुए हैं, इनमें से राजस्थान में ही देश के 20 प्रतिशत से अधिक यानी 103 ब्लॉक आवंटित हुए है। वहीं, राज्य सरकार के गत 18 माह के अल्प कार्यकाल में ही 64 ब्लॉकों का ऑक्शन हो चुका है। इस उपलब्धि के बाद राज्य सरकार सभी ब्लॉक्स के शीघ्र परिचालन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है ताकि प्रदेश में निवेश और राजस्व की वृद्धि अधिक से अधिक हो सके राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर अवैध खनन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की मंशानुसार खान विभाग ने एक्सप्लोरेशन, डेलिनियेशन, ब्लॉक निर्माण और पारदर्शी ऑक्शन की प्रभावी योजना पर कार्य किया है। जिसके अंतर्गत मिनरल ब्लॉक्स के निस्तारण के संबंध में त्वरित निर्णय

लिए जा रहे है। सरकार के गठन के तीन माह के भीतर ही (मार्च 2024 तक) 15 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से कर दी गई। वहीं, वर्ष 2024-25 में अकेले 34 ब्लॉकों की नीलामी कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया गया। खान विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 में जुलाई तक 15 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है और 12 ब्लॉकों की प्रक्रिया जारी है। वहीं, खान विभाग ने रॉयल्टी राजस्व में एक नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2024-25 में रॉयल्टी राजस्व 9 हजार 228 करोड़ रहा है, जो गत वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक है। नीलाम किए गए ब्लॉकों को जल्द परिचालन में लाने की दिशा में राज्य सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है ताकि निवेश, रोजगार और राजस्व में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो सके। खान विभाग ने जुलाई माह में राजस्व, वन एवं पर्यावरण, भारतीय खान ब्यूरो और स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (सिया) सहित संबंधित विभागों और स्टेकहोल्डर्स को एक मंच पर लाकर खनिज ब्लॉकों और प्लॉटों के परिचालन को गति देने की अभिनव पहल की है। साथ ही, विभाग ने आगामी नवंबर-दिसंबर तक 10 नई खानों को परिचालन में लाने की रणनीति भी बना ली है। प्रशासनिक अनुमतियों को तेजी से निस्तारित करने के लिए पोस्ट-ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल का गठन भी किया गया है, जो विभिन्न विभागों व स्टेकहोल्डर्स के बीच समन्वय स्थापित कर रहा है। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान की उपलब्धि का कारण पारदर्शी और प्रभावी ऑक्शन प्रक्रिया है, जिसकी सराहना केन्द्र सरकार ने भी की है। भारत सरकार के खान मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में कोणार्क, ओडिशा में आयोजित राज्य खनन मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में खनिज ब्लॉकों की नीलामी में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए राजस्थान को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया।

ऑटो में सवारी बिठाकर लूट करने का आरोपी गिरफ्तार

देश का दर्पण न्यूज
श्रीमती तेजस्विनी गौतम आईपीएस पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व ने बताया कि, पुलिस थाना सांगानेर जयपुर पूर्व पर दिनांक 13/07/2025 को शाम करीब 8 बजे के आस पास चाकसु बस स्टेण्ड सांगानेर टोंक रोड पर खड़ा होकर बस का इन्तजार कर रहा था काफी देर इंतजार करने पर भी बस नही आयी तो मैने एक ऑटो वाले से चाकसू चलने के लिए कहा 200 रुपये में ऑटो वाले ने चाकसु ले जाने की हां भरी ओर मै उसमे बैठ गया हल्दी घाटी रोड पर जाते ही उसने मुझसे कहा की पैसे दे दो बाद मे लेट हो जायेंगे मैने घर जाकर पैसे देने की बात कही पर वह नहीं माना तो मैने 200 रुपये मेरे दोस्ते शाहरुख खान से ऑटो वाले के स्कैनर पर करवाये। हल्दी घाटी गेट जाते ही उसने अपना ऑटा नाले की तरफ घुमा दिया और नाले पर ले जाकर हाथापाई की व ऑटा से धक्का देकर निचे गिरा दिया और मेरा मोबाइल नारजो कम्पनी का था छीन लिया और उसी दिन मै एक नया फोन डढढड अ5 5ॠ लाया था वो भी ओरिजनल विल सहित छीन लिया और मुझे वही पटक 2000 रुपये छीन लिया और भाग गया। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 304/2025 धारा 303 (2) बी.एन.एस. मे दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया

गया प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व श्री आशाराम चौधरी आरपीएस के नेतृत्व में श्री विनोद शर्मा आरपीएस सहाय पुलिस आयुक्त सांगानेर के निकट सुपरविजन में श्रीनिवास जांगिड पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना सांगानेर के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए मुल्जिम राकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया।।
गठित टीम द्वारा चालानशुदा मुल्जिमानों से पूछताछ की गई एवं तरीका वारदात के आधार पर घटनास्थल के आस पास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये एवं अपहताओं द्वारा अपहत को जंहा जंहा पर लेकर गये वंहा के सीसीटीवी कैमरे चैक किये गये। टीम द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग एवं महत्वपूर्ण आपराधिक आसूचना संकलित करते हुए तथा तकनिकी आधार पर प्रकरण में वांछित मुल्जिम राकेश मीणा को गिरफ्तार किया गया।

ओली सरकार को झटका, राष्ट्रपति का संवैधानिक परिषद विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार

काठमांडू। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की सरकार को आज उस समय तगड़ा झटका लगा जब राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संवैधानिक परिषद (कर्तव्य, कार्य, अधिकार और प्रक्रिया) अधिनियम, 2006 से संबंधित संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रतिनिधि सभा को वापस कर दिया है।
राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल के अनुसार, विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए गुरुवार को वापस भेज दिया गया था। पोखरेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को मूल सदन को यह कहते हुए वापस कर दिया कि प्रस्तावित संशोधन संविधान की भावना और सिद्धांतों, लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों तथा अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रथाओं के विपरीत है। राष्ट्रपति की तरफ से यह कदम संविधान के अनुच्छेद 113 (3) के तहत उठाया गया है।

न्यूज फ्लैश

अननौन कैफे धारिवाल चैम्बर के पास संचालित रेस्टोरेन्ट में अवैध हुक्का पर की गई कार्यवाही

देश का दर्पण न्यूज
श्री राजर्षि राज आई.पी. एस. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) जयपुर द्वारा जिला जयपुर दक्षिण में अवैध हुक्का बार संचालन को गंभीरता से लेते हुए इनके विरूद्ध त्वरित कार्यवाही हेतु निरन्तर निर्देश दिये जाने की पालनार्थ आज दिनांक 24.07.2025 को श्री ललित किशोर शर्मा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) के निर्देशन एवं श्री बालाराम आरपीएस सहायक पुलिस आयुक्त अशोकनगर जयपुर (दक्षिण) के निकट सुपरविजन में श्रीमती संतरा मीना पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना ज्योतिनगर जयपुर (दक्षिण) के नेतृत्व में श्री ओमप्रकाश उप निरीक्षक मय जाप्ता श्री राकेश कुमार कानि. 11285 श्रीमती प्रियंका मकानि. 9824 को मुखबीर खास से प्राप्त ईत्तलानुसार धारीवाल चैम्बर लालकोठी ज्योतिनगर जयपुर में स्थित अननौन कैफे को चैक किया गया तो उक्त कैफे में अवैध रूप से हुक्का संचालन पाया जाने पर कार्यवाही करते हुये अवैध हुक्का पीते हुए मिले 12 व्यक्तियों की 200/- प्रति व्यक्ति कोटपा एक्ट के तहत रशीद काटी जाकर कुल 2400/- रुपये जुमार्ना प्राप्त किया तथा कैफे के अन्दर मिले अवैध हुक्का सामग्री 8 हुक्के मय चिलम मय 13 पाईप तथा अवैध हुक्का तम्बाकु फ्लेवर के 09 खुले डिब्बे सामग्री जब्त की जाकर मैनेजर के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये अभियोग दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत जिला जयपुर उत्तर से 6 अपराधी तड़ीपार

देश का दर्पण न्यूज
श्री करन शर्मा पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) ने बताया कि विभिन्न अपराधों को अन्जाम देकर समाज में भय और आतंक का माहौल निर्मित करने वाले आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों के खिलाफ जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में आज जिले से 6 अपराधियों को पन्द्रह दिवस से एक माह की समयावधि के लिये जिला बदर किया गया है। जिला बदर (निष्कासन) के दौरान निम्न सभी अपराधियों को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, टोंक व अजमेर जिले में निष्कासित किये गये स्थान पर रहना होगा तथा सम्बंधित थाने में समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। समयावधि पूर्ण होने से पूर्व बिना अनुमति जिला जयपुर की सीमाओं के किसी भाग में प्रवेश नहीं करेंगें।
1.नोमान पुत्र मोहम्मद केमर उर्फ कमर बेग उम्र 23 साल निवासी म.न. 1331 मक्का मस्जिद के सामने थाना शास्त्रीनगर जयपुर।
2.आसिफ पुत्र अब्दुल मजीद उम्र 33 साल निवासी म.न. 240 पेन्टर कॉलोनी थाना शास्त्रीनगर जयपुर।
3.अनिल चौहान पुत्र रामस्वरुप मडभून्जा उम्र 24 साल निवासी म.न. 39-40 देशभूषण नगर आनन्दबाडी दिल्ली बायपास रोड थाना गलतागेट जयपुर।
4.राधाकिशन पुत्र फुलचन्द महावर उम्र 35 साल निवासी म.न. ई-102 कल्ली का भटटा नाग तलाई कच्ची बस्ती थाना गलतागेट जयपुर।
5.मौहम्मद राजा कुरेशी पुत्र मौहम्मद बफाती कुरेशी उम्र 30 साल निवासी म.न. 2963 भिण्डो का रास्ता चांदपोल बाजार कोतवाली थाना कोतवाली जयपुर।
6.मोहम्मद मुस्तफा पुत्र मोहम्मद युनुस उम्र 38 साल निवासी म.न. 4253 लोकनायक व्यास कॉलोनी थाना शास्त्रीनगर जयपुर।

सी.एस.टी. (क्राइम ब्रांच) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा ऑपरेशन "क्लीन स्वीप" के तहत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ थाना मुहाना में कार्यवाही

देश का दर्पण न्यूज
पुलिस आयुक्त श्री बीजू जॉर्ज जोसफ के मार्गदर्शन में जयपुर शहर में नशा तस्करों के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन "क्लीन स्वीप' मादक पदार्थों के विरूद्ध श्री मनीष अग्रवाल अति. पुलिस आयुक्त (अपराध) के निर्देशन में जयपुर शहर में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु श्री रिछपाल सिंह, अति. पुलिस उपायुक्त, संगठित अपराध, आयुक्तालय जयपुर के निकट सुपरविजन में उ.र.ळ. आयुक्तालय जयपुर के नेतृत्व में टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये आसूचना संकलन कर सूचनाओं पर पुलिस थाना मुहाना जयपुर (दक्षिण) की टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये अवैध मादक पदार्थों के विरूद्ध तस्कर प्रिंस मालावात पुत्र श्री मुकेश मालावत को गिरफ्तार कर कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक 256 ग्राम एवं परिवहन में प्रयुक्त 01 बिना नम्बरी मोटरसाईकिल को बरामद करने में सफलता अर्जित की गयी। उपरोक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में पुलिस थाना मुहाना जयपुर (दक्षिण) में मुकदमा नम्बर 758/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज कर अन्वेषण जारी है। उक्त कार्यवाही में सीएसटी से हैड कानि. रामकिशन की अहम भूमिका रही।

फायरिंग की वारदात में शामिल मुख्य अपराधी विकास यादव को बापर्दा किया गिरफतार

देश का दर्पण न्यूज
पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) IPS तैजस्वनी गौतम ने बताया कि दिनांक 18.07.2025 की रात्रि के दौरान थाना बजाज नगर ईलाका क्षेत्र शहिद के गटटे के पास टॉक रोड पर राह चलते लोगो पर हुई फायरिंग की घटना को गम्भीरता को देखते हुए वारदात में शामिल अपराधियों की धर पकड़ के लिये टीमें गठित की गई तथा श्री आशाराम चौधरी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व के सुपरविजन एवं श्री आदित्य पुनिया सहायक पुलिस आयुक्त मालवीय नगर के दिशा निर्देशन एवं श्रीमति पूनम चौधरी थानाधिकारी पुलिस थाना बजाज नगर के नेतृत्व में थाना बजाज नगर जयपुर पूर्व की टीम गठित की गई। टीम के सदस्यों द्वारा दिन रात कडी मेहनत करते हुए तकनिकी सहायता व आसुचना संकलित की गई तथा सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस की तकनिकी का प्रयोग किया गया। विभिन्न टीम ने जयपुर व कोटपुतली शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में रहकर लगातार अभियुक्तगण की तलाश की गई तथा कई संदिग्धो एवं परिचितो से पूछताछ की गई। मुखबिरो से प्राप्त जानकारी एवं वारदात में प्रयुक्त कार के नम्बर निकाल कर अपराधियो की पहचान की जाकर मुल्जिमान के हर सम्मावित ठिकानो पर दबिश दी गई। कठिन परिश्रम करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद पकडे जाने के डर से रात्रि में अंधेरा का फायदा उठाकर भागने वाले मुख्य अपराधी

विकास यादव को थाना बजाज नगर जयपुर पूर्व की टीम के सदस्यो ने पकड कर अनुसंधान अधिकारी के समक्ष किया जिसको बाद अनुसंधान प्रकरण संख्या 277/2025 धारा 109(2), 3(5) इढर व धारा 3/25, 5/27 आर्म्स एक्ट में दिनांक 22.07.2025 बापर्दा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेसी दाखिल करवाया गया है तथा विधि से संघर्षरत बालक को बापर्दा डिटेन कर बाद अनुसंधान बाल सुधार गृह में भिजवाया गया है। गिरफतारशुदा अपराधी विकास यादव व विधि से संघर्षरत बालक की परिवादी से शिनाख्तगी कार्यवाही करवाई जाकर पुनः अपराधी विकास यादव को अनुसंधान हेतु न्यायालय के आदेश से पीसी रिमाण्ड प्राप्त कर मुल्जिम के कब्जे से प्रकरण की वारदात में प्रयुक्त हथियार को बरामद किया जावेगा तथा शेष अपराधियो की तलाश कर गिरफतार किया जावेगा। प्रकरण गिरफतारशुदा मुल्जिम विकास यादव व विधि से संघर्षरत नाबालिक बालक ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनके अन्य साथी मोनू धनकड, जसराज गुर्जर उर्फ जस्सी दिनांक 18.07.2025 को रात्रि के समय मौज मस्ती करने व मोबाईल लुटने की फिराक में टोंक रोड पर घूम रहे थे इस दौरान एक कार वाले का मोबाईल लुट कर आगे भागने लगे तो रास्ता बंद होने के कारण कार से नीचे उतरने लगे तो वह गाडी वाले हमारी कार के पीछे अपनी कार लगा दी जिसके बाद मैने व मेरे साथियो ने कार में से देशी पिस्टल निकाल कर कार वाले पर फायर कर दिया जिससे कार वाला बच गया और राह चलते दूसरे व्यक्ति के गोली जा लगी जिससे वह जमीन पर गिर पडा उसके बाद हम डर कर पैदल ही भाग गये थे।

बिहार शिक्षा विभाग में बेल्ट्रॉनकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर: 22,000 कर्मचारियों का भविष्य अधर में....

संवाददाता मसरूर अहमद
पटना, 24 जुलाई, 2025 बिहार शिक्षा विभाग में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी बॉय 22 जुलाई, 2025 (मंगलवार) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। राज्यस्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच (गोप गुट) ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यह कदम उठाया है, जिससे राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं और विभागीय कार्यों पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
यह हड़ताल तब शुरू हुई जब 15 जुलाई, 2025 तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, जैसा कि मंच ने चेतावनी दी थी। हड़तालरत कर्मचारियों में से कुछ ने अपनी व्यथा व्यक्त की है:
मोहम्मद अमर अली कहते हैं, "हम पिछले 20 सालों से पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। सरकार को हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए।"
आशीष पाण्डेय ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "हमारे भविष्य अधर में है। हम केवल अपनी सेवाओं को नियमित करने और उचित वेतन व भत्ते की मांग कर रहे हैं।"
मनीष पाण्डेय ने कहा, "हमारी मुख्य मांग पदों का सृजन और हमारा वर्तमान कार्यालयों में समायोजन है। यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।"
कौशल कुमार और वेदप्रकाश सिंह ने सामूहिक रूप से कहा, "हम चाहते हैं कि सेवा वापसी या समाप्ति से पहले अपील का प्रावधान हो और हमें उचित वेतन वृद्धि मिले।"
सनी कुमार ने ग्रेच्युटी और अनुग्रह अनुदान की मांग पर जोर देते हुए कहा, "सेवानिवृत्ति के बाद 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान मिलना चाहिए।"
मोहम्मद हातिम ने अनुकम्पा नियुक्ति और वन-टाइम एडजस्टमेंट की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, "बेल्ट्रॉन के पत्रांक-4565/2021 दिनांक 22.09.2021 को लागू करते हुए कार्यरत कर्मियों की मृत्यु पर उनके आश्रित को उनकी योग्यता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए। साथ ही, सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली का गठन कर हमारा विभागों में एकमुश्त समायोजन (डल्ली-ळ्ी अ्४िर३ीेल्ल३) किया जाए।"

क्या है पूरा मामला?
बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (गोप गुट) से संबद्ध राज्यस्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच लंबे समय से राज्य सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। इससे कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है।
मंच ने जानकारी दी है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों, आयोगों सहित जिला मुख्यालयों से लेकर अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और पंचायत स्थित कार्यालयों में लगभग 22,000 (बाईस हजार) कर्मी कार्यरत हैं। ये सभी कर्मी पिछले लगभग 20 वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ विभागीय कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं।
प्रमुख मांगें:
कर्मियों की मुख्य मांगों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
* पदों का सृजन और समायोजन: बेल्ट्रॉन के पत्रांक 7541/18 दिनांक 01.11.2018 और 4309/19 दिनांक 10.07.2019 के आलोक में वर्तमान में कार्यरत बल के आधार पर पदों का सृजन कर, कर्मियों को बिना किसी शर्त पदस्थापित कार्यालयों में समायोजित किया जाए।
* सेवा वापसी/समाप्ति से पूर्व अपील का प्रावधान: सेवा वापसी या समाप्ति से पहले अपील करने का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, जैसा कि इढरट के कर्मियों के संदर्भ में लागू है।
* वेतन पुनरीक्षण: महंगाई को देखते हुए 01.01.2025 को आधार मानकर वेतन पुनरीक्षण किया जाए।
* ग्रेड अपग्रेडेशन: 03 वर्ष और 10 वर्ष पूरे होने पर कर्मियों को क्रमशः ग्रेड-01 और ग्रेड-02 में उत्क्रमित करते हुए आर्थिक लाभ प्रदान किया जाए।
* पुनः नियोजन: बेल्ट्रॉन के पत्रांक-टढ-18/24 दिनांक 09.01.2024 को रद्द करते हुए, सेवा वापसी के उपरांत बिना किसी शर्त पूर्व से प्राप्त हो रहे मानदेय तथा वरीयता के आधार पर पुनः नियोजन किया जाए (गंभीर आरोपों को छोड़कर)।
* भत्ते: चिकित्सीय, परिवहन, आवासीय और स्थानांतरण भत्ता प्रदान किया जाए।
* गृह जिला में स्थानांतरण: कर्मियों का पदस्थापन/स्थानांतरण उनके गृह जिला में किया जाए।
* ग्रेच्युटी: सेवानिवृत्ति के पश्चात ग्रेच्युटी के रूप में 20 लाख रुपए एकमुश्त राशि प्रदान की जाए।
* अनुग्रह अनुदान: सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1552 दिनांक 09.11.2015 और संकल्प संख्या-1520 दिनांक 10.12.2018 को संशोधित करते हुए सेवा अवधि के दौरान मृतक के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि 04 लाख रुपए के स्थान पर 20 लाख रुपए की जाए।
* अनुकम्पा नियुक्ति: बेल्ट्रॉन के पत्रांक-4565/2021 दिनांक 22.09.2021 को लागू करते हुए कार्यरत कर्मियों की मृत्यु पर उनके आश्रित को उनकी योग्यता के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए।
* वन-टाइम एडजस्टमेंट: जल्द से जल्द सूचना प्रावैधिकी संवर्ग नियमावली का गठन करते हुए उपर्युक्त कर्मियों को बिना किसी शर्त विभागों में एकमुश्त समायोजन (डल्ली-ळ्ी अ्४िर३ीेल्ल३) करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सरकार को चेतावनी:
एकता मंच ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि 15 जुलाई, 2025 तक उनकी संलग्न मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, तो राज्य के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित बेल्ट्रॉन कर्मी 17 जुलाई, 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। चूंकि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, 22 जुलाई से हड़ताल जारी है।
इसके अतिरिक्त, मंच ने स्पष्ट किया है कि यदि हड़ताल अवधि के दौरान किसी भी कर्मी पर दंडात्मक कारवाई की जाती है, तो हड़तालरत कर्मी उसी तिथि से भूख हड़ताल प्रारंभ कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार और संबंधित विभाग/निगम की होगी।
इस हड़ताल से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है, खासकर शिक्षा विभाग में, जहां बड़ी संख्या में डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी बॉय कार्यरत हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी और जल्द ही कोई समाधान निकलेगा?

सीवान नगर परिषद में भ्रष्टाचार का गहराता जाल: अनियमितताओं, कमीशनखोरी और जनप्रतिनिधियों की संलिप्तता का विस्तृत विश्लेषण

सीवान संवाददाता मसरूर अहमद
सीवान, बिहार: सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता प्रयाग कुमार ने सीवान नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे शहर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का गहराता जाल बेनकाब हुआ है। उनके अनुसार, सीवान नगर परिषद में जनता के पैसे का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। यह स्थिति शहर के बुनियादी ढांचे को सुधारने के बजाय, ठेकेदारों, अधिकारियों और कुछ जनप्रतिनिधियों की सांठगांठ से व्यक्तिगत लाभ कमाने का आरोप लगा रही है, जिससे शहर का विकास अवरुद्ध हो रहा है और आम जनता का भरोसा टूट रहा है।
घटिया निर्माण काय्: जल निकासी और सड़कों की बदहाली का मुख्य कारण
शहर में नालियों का निर्माण मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है, जिसका सीधा परिणाम यह है कि बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। नालियां या तो अधूरी छोड़ दी जाती हैं या उनकी चौड़ाई और गहराई इतनी कम होती है कि वे पानी का भार झेल नहीं पातीं।
इसी तरह, सड़कों के निर्माण में भी गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। आलम यह है कि नई बनी सड़कें एक साल के भीतर ही टूट-फूट का शिकार हो जाती हैं। इन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आश्चर्य की बात यह है कि इन गंभीर मुद्दों पर न तो नगर परिषद के अधिकारी ध्यान देते हैं और न ही जूनियर इंजीनियर। ऐसा लगता है कि निर्माण स्थलों का निरीक्षण शायद ही कभी किया जाता है, जिससे ठेकेदारों को अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल जाती है। ठेकेदार बिना किसी डर के निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करते हैं और काम को अधूरा छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराएगा।
टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली: 'टेबल टेंडर' का खेल
नगर परिषद में सबसे गंभीर आरोपों में से एक टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली है। सूत्रों के अनुसार, शहर में होने वाले अधिकांश टेंडरों को अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर जानबूझकर छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। ये टुकड़े इस प्रकार बनाए जाते हैं कि प्रत्येक टेंडर की अनुमानित लागत \३ी७३त्न?त्न14 लाख से कम हो जाए। ऐसा करने के पीछे का मकसद स्पष्ट है: \३ी७३त्न?त्न14 लाख से कम के टेंडरों को 'टेबल टेंडर' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके लिए खुली निविदा प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती।
इसका परिणाम यह होता है कि ये टेंडर खुले तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बजाय, नगर परिषद के भीतर ही अपनी पसंद के ठेकेदार को दे दिए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में ठेकेदारों से मोटा कमीशन वसूला जाता है, जो कथित तौर पर संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच बांट लिया जाता है। यह स्पष्ट रूप से सरकारी नियमों, पारदर्शिता और निष्पक्षता का सीधा उल्लंघन है। इस प्रथा से योग्य और ईमानदार ठेकेदारों को अवसर नहीं मिल पाता और अंततः इसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कार्यों की गुणवत्ता से समझौता किया जाता है।
जनप्रतिनिधियों पर ठेकेदारी का आरोप: हितों का टकराव और भ्रष्टाचार का प्रोत्साहन
चिंताजनक रूप से, कई जगहों से यह भी सुनने को मिल रहा है कि कुछ पार्षद स्वयं ही ठेकेदार बन गए हैं या उन्होंने अपने किसी करीबी रिश्तेदार या विश्वसनीय व्यक्ति के नाम पर ठेकेदारी ले रखी है। यह स्थिति हितों के सीधे टकराव को दर्शाती है। जब जनप्रतिनिधि, जिनका कर्तव्य जनता के हितों की रक्षा करना और विकास कार्यों की निगरानी करना है, स्वयं ही ठेकेदारी करने लगते हैं, तो वे अपनी निजी लाभ को प्राथमिकता देंगे।

सिवान: कोर्ट के वारंट के बाद भी अभीयुक्त तौफिक अहमद देश छोड़ फरार....

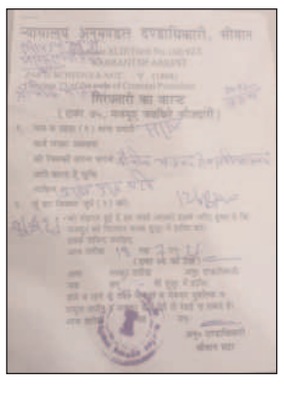

सीवान संवाददाता मेराज अहमद
सिवान, न्यायालय द्वारा वारंट जारी किए जाने के बावजूद सिवान के सराय थाने की पुलिस कथित तौर पर अपराधियों को गिरफ्तार करने में विफल रही है, जिससे उनके कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिवक्ता मसरूर अहमद के निजी भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में, अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष कई बार सुनवाई के बावजूद विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण

कोर्ट ने वारंट जारी किया था।
ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस की छापेमारी जारी है, लेकिन अभियुक्त तौफीक अहमद देश छोड़ कर फरार है, जबकि दूसरा अभियुक्त वकीस अहमद , ताबीस इरशाद, कथित तौर घर छोड़कर भाग गया है। यह स्थिति सराय थानाध्यक्ष धर्मेंद्र पर पहले से लगे आरोपों को और पुख्ता करती है कि वे उच्चाधिकारियों के आदेशों और न्यायिक निर्देशों को भी नजर अंदाज कर रहे हैं। अहमद का आरोप है कि उनकी ऋक्र दर्ज करने से लगातार इनकार किया जा रहा है, जिससे "पैसा दो, ऋक्र पाओ" जैसे गंभीर आरोप सराय थाने पर लग रहे हैं।
यह घटना दर्शाती है कि "सुशासन बाबू" के राज में भी आम जनता को न्याय के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि सराय थानाअध्यक्ष की कथित मनमानी और भ्रष्टाचार चरम सीमा और पोल को दर्शाता है।

नितिन गडकरी ने इंटरनेशनल शुगर एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल शुगर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शुगर इंडस्ट्री में हो रहे अनुसंधान और नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञान ही भविष्य है और इसे संपत्ति में बदलना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

यात्री का मोबाईल चोरी करने वाला शातिर को किया गिरफतार

देश का दर्पण न्यूज
पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम श्री हनुमान प्रसाद मीणा आईपीएस ने बताया कि परिवादी श्री सोनू गोचर ने दर्ज करवाया कि मैं दिनाँक 23.07.2025 को समय करीब 12.30 बजे दोपहर खासाकोठी पुलिया के नीचे बने कोम्पलेक्स में हाथ मुंह धोकर निकला मेरे हाथ में मेरा मोबाईल फोन ले कर जा रहा था तो अचानक एक व्यक्ति ने मेरा मोबाइल फोन वीवो ए54 रंग काला सिम न. 8890352606 लगी हुई को छीन लिया मेरे विरोध करने पर उस व्यक्ति ने एक चाकुनुमा हथियार दिखा कर मुझे धमकाया की अगर तुने मुझे पकडने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। मैं डर गया और वो व्यक्ति मेरा मोबाइल छिन कर भाग गया। उस व्यक्ति की उम्र 35-40 साल होगी तथा उसने मेहरुन कलर की हाफ बाजु की टी-शर्ट पहन रखी थी रिपोर्ट करता हूं कानूनी कार्यवाही करें। आदि पर मुकदमा नं0 114/2025 धारा 307 भारतीय न्याय संहिता दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
प्रकरण की वारदात की गंभीरता को देखते हुये एवं बस स्टैण्ड पर यात्रीयों के सामान, मोबाईल, पर्स इत्यादि घटनाओं की रोकथाम हेतू श्री आलोक सिंघल अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम एवं श्री धर्मवीर सिहं सहायक पुलिस आयुक्त सदर जयपुर पश्चिम के निकट सुपरविजन में श्री श्याम सुन्दर उप०नि० थानाधिकारी पुलिस थाना सिंधीकैम्प जयपुर पश्चिम के नेतृत्व में थाना हाजा पर विशेष टीम का गठन किया गया गठित टीम सदस्यों द्वारा कडी मेहनत कर आसुचना संकलन करते हुये मुल्जिम अनिल शर्मा को गिरफतार किया गया एवं मुल्जिम से प्रकरण हाजा में वांछित माल मशरूका एक मोबाईल फोन को बरामद किया गया एवं मुल्जिम के पास मिला एक धारधार चाकू को जब्त किया गया। मुल्जिम से अन्य वारदातों के बारे में तफतीश की जा रही हैं।

कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, बीकानेर हाउस में तीज मेले का भी किया अवलोकन

जयपुर, 24 जुलाई। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की।

श्री कुमावत ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह से भेंट कर उन्हें राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नवाचारों की जानकारी दी। श्री कुमावत ने विभाग द्वारा अब तक किए गए उल्लेखनीय कार्यों का संकलन ह्यप्रगति पुस्तिकाह्न के रूप में भेंट कर केंद्रीय मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने राजस्थान के लिए पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं, योजनाओं में केंद्रीय अंश बढ़ाने तथा भावी सहयोग को लेकर विस्तृत चर्चा की एवं संबंधित मांगें उनके समक्ष प्रस्तुत की।

इसी क्रम में श्री कुमावत ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री कुमावत ने उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने पशुपालन विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करती पुस्तिका भी केंद्रीय मंत्री को भेंट की।

कैबिनेट मंत्री श्री कुमावत ने नई दिल्ली में पाली लोकसभा से सांसद एवं 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (खढउ) के चेयरमैन श्री पी. पी. चौधरी से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पाली लोकसभा सहित राजस्थान से जुड़े विभिन्न जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा की।

बीकानेर हाउस में तीज मेले का किया अवलोकन,बीकानेर हाउस में खुलेगा सरस पार्लर–

मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बृहस्पतिवार को अपने दिल्ली प्रवास के दौरान नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक चलने वाले तीजोत्सव और हस्तशिल्प मेले का अवलोकन किया। इस दौरान श्री कुमावत ने कहा कि राजस्थानी कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऐसे मेले मिल का पत्थर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की देश-विदेश में लगातार मांग बढ़ रही है और राज्य सरकार भी उन्हें बढ़ावा देने के प्रतिबद्ध है। श्री कुमावत ने मेले में लगे स्टालों पर व्यक्तिश जाकर राजीविका और रूडा के विक्रेता कारीगरों का उत्साहवर्धन किया तथा उनके उत्पादों की सराहना की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री जोराराम कुमावत ने कहा की राजधानी में राजस्थान की सरस डेयरी के दुग्ध उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है तथा बीकानेर हाउस में सरस पार्लर खोलने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

दिल्ली में आयोजित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में माननीय श्री रामदास आठवले को एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया।

नई दिल्ली/जयपुर, जुलाई 2025। इस बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नव-निर्वाचित सदस्यों का भी चयन किया गया। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति पर RPI (आठवले) राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राधा मोहन सैनी ने श्री आठवले सहित सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि श्री आठवले के नेतृत्व में पार्टी सामाजिक न्याय और दलित सशक्तिकरण के लिए लगातार संघर्षरत रही है और आने वाले समय में संगठन और अधिक सशक्त होकर जनहित में कार्य करेगा। कार्यकारिणी बैठक में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक निर्णय भी लिए गए, जिससे पार्टी को देशभर में मजबूती मिलेगी।

एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय में आज मनाया जाएगा सावन तीज महोत्सव

कैथल (कृष्ण प्रजापति): एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल में 25 जुलाई को सावन तीज महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणवी और पंजाबी लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसको लेकर जानकारी देते हुए विश्विद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ मनोज ग्रोवर ने बताया कि पेड़ों पर झूले, सावन की फुहार... बधाई हो आपको, आया तीज का त्योहार इस के संदेश के साथ आयोजित यह तीज महोत्सव परंपरा, रंग और उत्सव का सुंदर संगम होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी गणमान्य व्यक्तियों और विद्यार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे शुरू होगा जोकि बहुद्देशीय सभागार, एनआईआईएलएम विश्वविद्यालय, कैथल में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में हरियाणवी और पंजाबी पारंपरिक लोक नृत्य व गीतों की प्रस्तुतियां, तीज महोत्सव की कहानी पर आधारित सत्र, मेहंदी कला प्रतियोगिता, चूड़ी सजावट प्रतियोगिता आयोजित होगी।

विश्वविद्यालय की छात्राओं और संकाय सदस्यों में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। डॉ मनोज ग्रोवर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है, जिससे वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राध्यापकगण, विद्यार्थी और अतिथिगण उपस्थित रहेंगे। तीज महोत्सव के माध्यम से नारी शक्ति, पारंपरिक कलाओं और लोक संस्कृति को सजीव रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

धान के खेत में मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

रमेश राय, कोलकाता –

दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप इलाके में गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई, जब धान के खेत से एक युवक का रक्तरंजित शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान राकिब शेख (27) के रूप में हुई है, जो मधुसूदनपुर ग्राम पंचायत के रामतनुनगर का निवासी था।

स्थानीय ग्रामीणों ने सुबह खेत में राकिब का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा देखा और तुरंत हरवुड पॉइंट कोस्टल थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

राकिब के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतक चार नंबर बूथ के पंचायत सदस्य सलाउद्दीन शेख का भतीजा था। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या किसी अन्य कारण से उसकी मौत हुई है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। क्षेत्र में तनाव का माहौल है, वहीं स्थानीय लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

विधायक ने उठाया अपने क्षेत्र का मुद्दा

देश का दर्पण न्यूज (बिहार वैशाली) पातेपुर संवाददाता रंजीत कुमार

पातेपुर के विधायक लखेंदर पासवान ने मानसून सत्र के दौरान सदन में राज्य के सभी लोक स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर एवं राज्य के सभी पंचायतों के सभी वार्डों नल जल अनुरक्षको की राशि बढ़ाने की मांग राज्य की सरकार से की है। विधायक श्री पासवान के द्वारा सदन में अपनी बात रखते हुए कहा गया की वैक्सीन कुरियर वर्ष 2005 से स्वास्थ केन्द्र से वैक्सीन लेकर सभी पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाने का कार्य करता है। जिससे नियमित रूप से 0 से 5 वर्ष एवं गर्भवति महिलाओं को टीकाकरण किया जाता है। वहीं वैक्सीन कुरियर दवा पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। जिसमें उन लोगों को प्रत्येक केंद्र के हिसाब से मात्र 110 रुपए दिए जाते हैं जो दैनिक मजदूरी से भी कम है। विधायक ने वैक्सीन कुरियर को 250 रुपए देने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से की। वहीं विधायक ने राज्य के सभी पंचायतों के सभी वार्डों में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ग्राम सभा के माध्यम से नल जल अनुरक्षको की बहाली के बाद दो हजार रुपए मानदेय दी जाती है जो दैनिक मजदूरी से भी काफी कम है विधायक ने नल जल अनुरक्षको का मानदेय बढ़ा कर 10000 रुपए करने की मांग राज्य सरकार से की है। विधायक के इस पहल से कुरियर कर्मी एवं नल जल अनुरक्षको में खुशी की लहर दौड़ गई है एवं उन लोगों ने विधायक के प्रति आभार प्रकट करते हुए विधायक को बधाई दी है।

भ्रष्टाचार और बायपास की खस्ताहाली को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल व प्रदर्शन राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, दोषियों पर कार्रवाई की उठी मांग

सुरज वर्मा

शाहपुरा शहर में भ्रष्टाचार और बायपास सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर गुरुवार को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।उपखंड मुख्यालय पर आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेसजनों ने 10 किलोमीटर लंबे अधूरे और गड्ढों में तब्दील शाहपुरा बायपास निर्माण में हुई अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकताओं ने 'भ्रष्टाचार मुदार्बाद' और 'जनता का पैसा वापस दो' जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन को जमकर घेरा।प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी राजेश मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई तथा अधूरे बायपास निर्माण को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बायपास का लोकार्पण अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी इसमें बड़े-बड़े गड्ढे और निर्माण की खामियां स्पष्ट दिख रही हैं, जो कि बड़े स्तर के घोटाले की ओर इशारा करती हैं।

इस अवसर पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रत्याशी नरेंद्र रेगर, रमेश सेन, जयंत जीनगर, रामप्रसाद धाकड़, ओम सिंधी, मिंकु रविंदत, अनिल शर्मा, नमन ओझा, विजय टेलर, ओम प्रकाश सेन, सुनील मिश्रा, अजय मेहता, सत्यनारायण पाठक, कालू पायक, अभिषेक गुड्डू त्रिपाठी, पंकज पाराशर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।कांग्रेसजनों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के माध्यम से "भ्रष्टाचार मुक्त शाहपुरा" की अपील भी की गई।

महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम का आयोजन

सुरज वर्मा

शाहपुरा में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना आरयूआईडीपी की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम के तहत कालिंजरी गेट पास परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। केप आरयूआईडीपी के सामाजिक विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राणावत ने स्वच्छता पर जानकारी देते हुए बताया कि आरयूआईडीपी के द्वारा एफएसटीपी का कार्य स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि सेप्टिक टैंकों का फिकल स्लज खुले में डालने के कारण किसी न किसी रूप में वापस अपने घरों तक पहुंच रहा है। हम कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए घरों के सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल जल को टैंकों में भरकर बन रहे एफएसटीपी में ले जाया जाएगा, वहां इसको ट्रीट कर खाद के रूप में खेतों में उपयोग में लिया जाएगा।

हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर गौशाला आसलपुर में हुआ भव्य गौसंकिर्तन कार्यक्रम

अजय सिंह (चिंटू)

आसलपुर, जयपुर – अमावस्या के शुभ अवसर पर सत्संग भवन, गौशाला आसलपुर में एक भव्य गौसंकिर्तन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन गौसेवा, भक्ति और समर्पण की अनूठी मिसाल बनकर सामने आया।

कार्यक्रम की शुरूआत गौमाता के पूजन एवं भजन संकीर्तन से हुई। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष जगदीशपुरी गोस्वामी एवं अन्य सदस्यों द्वारा भामाशाहों का स्वागत व अभिनंदन किया गया। आसलपुर गांव से पधारे गोभक्तों ने गो सेवा कर गौसंकिर्तन का श्रवण पान किया।

भजनों की मधुर स्वर लहरियों ने बांधा समां

भजन गायकों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर कर दिया। महेश सिरोहिया (गुढाबैरसल), मोतीलाल भूरोदिया, सरदार सिंह राव, रामप्रताप भूरोदिया, छोटूराम दम्बीवाल, लालाराम सिरोहिया, छोटूराम भूरोदिया तथा महिला गायक मानादेवी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दीं, जिस पर उपस्थित गौसेवक झूम उठे।

विशिष्ट उपस्थिति:

गौशाला संरक्षक पं. सुरेश शर्मा

कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष रामलाल कुमावत, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश जाजोरा, छीतरमल जाजोरा, संरक्षक बंशीलाल कुमावत, भागचंद कुमावत, मनोज कुमावत, नाथूलाल जाजोरा, गिरधारीलाल, गोविंद भूरोदिया, रमेश सिंह चारण, घासीलाल राजोरा, हेमराज सिरोहिया, रमेश जाजोरा, हंसराज, दिव्यांशु, पुष्पेन्द्र, पीयूष, खुशवंत जाजोरा सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में गौशाला समिति की ओर से सभी भामाशाहों एवं सहयोगियों का आभार प्रकट किया गया और गौसेवा को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया।

हरियाणा की 6500 किलोमीटर सड़कों की होगी मरम्मत, प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाना सरकार का लक्ष्य: मंत्री रणबीर गंगवा

कैथल, 24 जुलाई (कृष्ण प्रजापति):

हरियाणा सरकार ने राज्य में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 6500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का ऐलान किया है। इस महत्त्वपूर्ण कार्य को लेकर पंचकूला में आयोजित एक प्रेसवार्ता में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक इस परियोजना की 80 प्रतिशत टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

मंत्री गंगवा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश की सड़कों को पूरी तरह गड्ढा मुक्त बनाना है, ताकि आम जनता को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ठेकेदारों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करें।

सरकार की प्राथमिकताएं : अच्छी सड़कें, शुद्ध जल और बेहतर जन स्वास्थ्य

मंत्री रणबीर गंगवा ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ सड़कों की मरम्मत ही नहीं कर रही, बल्कि तीन अहम विषयों : अच्छी सड़कें, शुद्ध पेयजल और बेहतर जन स्वास्थ्य सेवाएं को प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शुद्ध जल आपूर्ति को लेकर नई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। नालियों, सीवरेज सिस्टम और पीने के पानी की पाइपलाइनों की भी व्यापक जांच की जा रही है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

जनता से की अपील

मंत्री गंगवा ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी सड़क निर्माण या मरम्मत कार्य में कोई लापरवाही या भ्रष्टाचार नजर आए, तो तुरंत संबंधित विभाग या प्रशासन को सूचना दें। सरकार हर शिकायत पर कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

प्रदेश में चर्चा है कि यह अभियान प्रदेश के संपूर्ण विकास की ओर एक ठोस कदम है। आने वाले समय में जब हरियाणा की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, जब हर घर में शुद्ध जल पहुंचेगा और जब हर व्यक्ति को बेहतर जनस्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तभी "सशक्त हरियाणा" का सपना साकार होगा।

साइन बोर्ड पर भी मंत्री सख्त

सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर भी मंत्री गंगवा ने चिंता जताई और सख्त निर्देश दिए कि प्रदेशभर में टूटे हुए या खराब हो चुके साइन बोर्ड्स को या तो ठीक किया जाए या उन्हें तुरंत बदला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि जनता के बीच सरकार की साख मजबूत हो।

मंत्री गंगवा ने कहा कि प्रदेश की प्रगति सड़क नेटवर्क और आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। इसीलिए सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करें और यह सुनिश्चित करें कि हर कार्य में गुणवत्ता सर्वोच्च स्तर की हो।

लैब में भेजे जाएं सैम्पल

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे भवन और सड़कों में लगने वाली सामग्री की क्वॉलिटी पर भी विशेष ध्यान रखा जाए और सामग्री की समय-समय पर विभाग की लैब में इनकी जांच करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जो भी कार्य पूरे हो जाते हैं और उनका उद्घटान हो गया हो तो उस भवन को सम्बंधित विभाग को सौंप दिया जाये। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद समय पर बिल की अदायगी कर दी जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, प्रमुख अभियंता अनिल दहिया, राजीव यादव, एचएसआरडीसी के एमडी वीएस मलिक भी मौजूद थे।

भारतीय जनता पार्टी, कैथल ने मंडल प्रभारियों की नई सूची जारी की

कैथल (कृष्ण प्रजापति): भारतीय जनता पार्टी, कैथल द्वारा जिला स्तर पर संगठनात्मक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज मंडल प्रभारियों की नई सूची जारी की गई है। भाजपा जिला अध्यक्षा ज्योति सैनी ने प्रदेश नेतृत्व से विचार-विमर्श के बाद यह नियुक्तियां की हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों गुहला, कलायत, कैथल और पुंडरी के अंतर्गत आने वाले मंडलों के लिए अलग-अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं।

गुहला विधानसभा के लिए नियुक्त प्रभारी:

गुहला: शीला मुंजाल

कांगथली: रघुबीर फौजी

सीवन: अवधेश किशोर राय

भागल: मांगे राम जिन्दल

कलायत विधानसभा के लिए नियुक्त प्रभारी:

कलायत: जंगीर सिसला

बालू: राममेहर शर्मा

राजौंद: अजय प्रताप राणा

जाखौली: कुलविन्द्र राणा

कैथल विधानसभा के लिए नियुक्त प्रभारी:

कैथल (शहरी): रविंद्र धीमान

क्योड़क: शक्ति सौदा एडवोकेट

पाडला: वीरेंद्र बतरा

चन्दाना गेट: आशा रानी

पुंडरी विधानसभा के लिए नियुक्त प्रभारी:

पुंडरी: राजेश बीढान एडवोकेट

ढांड: हर्ष सेठी

करोड़ा: रोशन सैनी

भाजपा जिला अध्यक्षा ज्योति सैनी ने कहा कि सभी नियुक्तियां संगठन को और अधिक सक्रिय, मजबूत और जमीनी स्तर तक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से की गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी प्रभारी पूरी निष्ठा और मेहनत से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

सीईटी परीक्षा में प्रजापति समाज का सेवा भाव : हरियाणा भर में समाजबंधु छात्रों के लिए कर रहे नि:शुल्क ठहरने व खाने-पीने की व्यवस्था

कैथल (कृष्ण प्रजापति): हरियाणा में सीईटी परीक्षा 26 और 27 जुलाई को आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन (बीपीएचओ) संगठन ने एक प्रशंसनीय पहल करते हुए प्रदेश भर में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क रात्रि विश्राम, भोजन एवं सहयोग की व्यवस्था की है। इस सेवा कार्य में प्रजापति समाज की विभिन्न धर्मशालाएं एवं समाजसेवी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रजापति गोहाना (मो. 9813977317), प्रदेश महासचिव विनोद डीग (मो. 8529006040) एवं कोषाध्यक्ष गोविंद प्रजापति महेंद्रगढ़ (मो. 9992220535) ने सभी परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे अपनी परीक्षा वाले जिलों में प्रजापति धर्मशालाओं या समाज द्वारा की गई व्यवस्थाओं में ठहरें। इन स्थानों पर रहने, खाने और अन्य जरूरी सहायता की सम्पूर्ण व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध है।

प्रदेशाध्यक्ष नरेश गोहाना ने बताया कि हरियाणा के लगभग 22 जिलों में विभिन्न समाजसेवी और पदाधिकारी इस कार्य में जुटे हुए हैं, जिनमें अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, दादरी, महेन्द्रगढ़, पलवल, नूंह, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पंचकूला, यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी शामिल हैं। हर जिले के लिए प्रमुख संपर्क व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, ताकि विद्यार्थियों द्वारा किसी भी समय किसी भी सहायता के लिए उनसे संपर्क कर सकें।

एक किरण उम्मीद की संस्था द्वारा मूंदड़ी में नि:शुल्क दंत जांच शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

पुंडरी (कृष्ण प्रजापति): सामाजिक संस्था "एक किरण उम्मीद की" द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मूंदड़ी में एक विशेष नि:शुल्क दंत जांच शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत जहां डेंटल सर्जन डॉ प्रांजल गाबा बीडीएस ने बच्चों के दांतों की जांच की, उन्हें टूथपेस्ट वितरित किए गए और दांतों की सफाई को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। वहीं डॉ. मनीषा मंगल ने छात्राओं को "गुड टच-बैड टच" तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय पर जागरूक किया गया। सिंगला डेंटल क्लिनिक पिहोवा चौक कैथल से पहुंची दंत चिकित्सका डॉ. प्रांजल गाबा ने विद्यार्थियों को दिन में 2 बार टूथ ब्रश करने की सलाह दी और खानपान पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस शिविर के संयोजक समाजसेवी सतबीर सिंह मूंदड़ी रहे जोकि लंबे समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य व शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। एक किरण उम्मीद की संस्था की पदाधिकारी निधि मोहन के अनुसार, यह शिविर विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के लिए आयोजित किया गया ताकि उन्हें समय रहते दंत स्वास्थ्य की जांच और सही जानकारी मिल सके। उन्होंने बताया कि एक किरण उम्मीद की संस्था समय-समय पर नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, पशु सेवा, शिक्षा प्रोत्साहन जैसे विभिन्न सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहती है। सतबीर मूंदड़ी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे आयोजन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की ओर एक सार्थक कदम हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल प्रिंसिपल सुरेश कुमार ने की। कार्यक्रम के अंत में सतबीर मूंदड़ी ने टीम को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। स्कूल प्रांगण में इस दौरान विद्यार्थियों, स्कूल स्टाफ सदस्यों और ग्रामीणों के साथ पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर संस्था पदाधिकारी वंदना मित्तल, नेहा, आस्था, ग्राम पंच डॉ सुरेश कुमार, शमशेर पंच, कुलदीप पंच, ग्रामीण बलबीर सिंह, रामधारी, सेवा राम, राजेश कुमार, एसएमसी प्रधान एवं चौकीदार कर्मवीर सिंह, कर्मबीर सहित स्कूल स्टाफ सदस्यों में खुशी राम, राजबीर, संदीप गोलन, पुष्पा , सुनीता, डॉ संतोष, गीता, भागवंती, पूजा, पारुल, ओमप्रकाश, रामेश्वर, संदीप किरण आदि उपस्थित रहे।

इस्लाम को हिंसा, असहिष्णुता और कट्टरता से जोड़कर देखा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : मौलाना सईदूर रहमान

कैथल, 24 जुलाई (कृष्ण प्रजापति): आज के दौर में इस्लाम को हिंसा, असहिष्णुता और कट्टरता से जोड़कर देखा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी संदर्भ में जमियत उलेमा-ए-हिंद के कैथल जिला अध्यक्ष मौलाना सईदूर रहमान ने एक विचारोत्तेजक और संतुलित बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लाम की सही समझ तब तक नहीं हो सकती जब तक हदीसों और कुरान को संदर्भ सहित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न पढ़ा जाए।

मौलाना सईदूर रहमान ने कहा कि हदीसें पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) के जीवन और संदेशों का प्रतिबिंब हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ तत्व इनका दुरुपयोग कर इस्लाम की छवि को कलंकित कर रहे हैं। उग्रवादी संगठनों द्वारा हदीसों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करना इस्लाम के असली संदेश, शांति, करुणा और न्याय से विश्वासघात है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पैगंबर ने महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और नेतृत्व के अवसर दिए। हजरत आयशा (र.अ.) जैसी महान विदुषी इसका प्रमाण हैं, जिनसे सैकड़ों सहाबा ने ज्ञान प्राप्त किया लेकिन आज कुछ लोग मनगढ़ंत कथनों के आधार पर महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जो कि इस्लाम की मूल भावना के विरुद्ध है।

मौलाना ने चिंता जताई कि कुछ शासक और प्रभावशाली लोग हदीसों का इस्तेमाल सत्ता को कायम रखने के लिए करते हैं। जालिम हाकिम की आज्ञा मानोह्न जैसे कथन संदर्भ से काटकर पेश किए जाते हैं, जिससे इस्लाम का मूल आधार, जवाबदेही और परामर्श कमजोर होता है। उन्होंने कहा कि हदीसों की गलत व्याख्या न केवल मुस्लिम समाज में भ्रम और टकराव को जन्म देती है, बल्कि गैर-मुस्लिमों के मन में भी इस्लाम को लेकर गलत धारणाएं पैदा करती है। इस चुनौती से निपटने के लिए शिक्षा, आलोचनात्मक सोच और प्रमाणिक धार्मिक मार्गदर्शन बेहद जरूरी है।

साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता

फर्जी दस्तावेजों पर सिम देने का था मामला

देश का दर्पण न्यूज
संवाददाता सुरेन्द्र कुमार सोनी
साइबर अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रही राजस्थान पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मोबाइल सिम कार्ड बेचकर साइबर अपराधों को बढ़ावा दे रहा था। इस मामले में पहले गिरफ्तार किए गए घनश्याम मीणा से मिली जानकारी के आधार पर जयपुर के मालपुरा गेट स्थित एक वोडाफोन स्टोर के दो कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव (CRE) कर्मचारियों को गिरफ्तार गया है। यह कार्रवाई साइबर क्राइम राजस्थान पुलिस ने की है, जिसने इस पूरे रैकेट का पदार्फाश कर दिया है। एसपी साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि 22 जुलाई को साइबर क्राइम पुलिस को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि मालपुरा गेट थाना क्षेत्र में एक युवक फर्जी कागजात के जरिए मोबाइल सिम खरीदने आया है। सूचना मिलते ही साइबर क्राइम, राजस्थान, जयपुर के थानाधिकारी अपनी टीम के साथ मालपुरा गेट स्थित भारती हेक्साकॉम लिमिटेड (एयरटेल) स्टोर पर पहुंचे।
स्टोर इंचार्ज दीपेंद्र शर्मा ने कंपनी के लेटरहेड पर दीपक बलवदा, नोडल ऑफिसर एयरटेल जयपुर की लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घनश्याम मीणा नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया।

उसके पास से 7 मोबाइल सिम कार्ड, 2 खाली सिम कवर, 2 आधार कार्ड और एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ।
कम्पनी कर्मचारियों की काली करतूत
एसपी शांतनु कुमार के सुपरविजन में जब घनश्याम मीणा से गहन पूछताछ की गई तो उसने ने बताया कि उसके पास से बरामद हुई तीन वोडाफोन सिम उसने मालपुरा गेट स्थित वोडाफोन स्टोर के कर्मचारियों से ली थीं। जांच में सामने आया कि स्टोर के कर्मचारी छाजूराम ने अपने सहकर्मी अभिषेक कुमार की मदद से यह गोरखधंधा चलाया हुआ था। जब स्टोर पर दूसरे ग्राहक सिम खरीदने आते थे तो अभिषेक उनके नाम से अतिरिक्त सिम निकाल लेता था और फिर छाजूराम के कहने पर ये अवैध सिम घनश्याम मीणा जैसे लोगों को बेची जाती थीं। आमने-सामने की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।
अनुसंधान के बाद वोडाफोन स्टोर के दोनों कर्मचारियों जिनकी इस अपराध में सीधी संलिप्तता पाई गई, को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमे
छाजूराम पुत्र राम किशन निवासी वार्ड नम्बर 1, डूमोली खुर्द, झुंझुनूं और अभिषेक कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी दुर्गा विहार देवली साउथ दिल्ली शामिल है। इस मामले में आगे की जांच जारी है और उम्मीद है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्य भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।

प्रदेश में खुशी की लहर

अच्छी बारिश से बीसलपुर बांध व नवनेरा बैराज भरे, गेट खोले गए
बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। 21 साल में यह पहली बार हुआ है कि जुलाई में ही बीसलपुर बांध भर गया है। यह बांध परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक के करीब एक करोड़ आबादी को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराती है। साथ ही, टोंक जिले के 256 गांवों में 81 हजार 800 हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है।
अच्छी बारिश के कारण नवनेरा बैराज बैराज भर चुका है और इसके गेट भी खोल दिए गए हैं। इससे अपस्ट्रीम में कालीसिंध नदी के आस-पास कुंओं और भूजल के स्तर में वृद्धि होगी।

अखिल भारतीय राजस्थान माली समाज के उपाध्यक्ष चुने गए भोपालगढ़ निवासी प्रिंस सैनी।

अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान पुष्कर के द्वारा सावन मास की हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर धन्यवाद ज्ञापन, कार्यकारिणी विस्तार एवं समान

समारोह का कार्यक्रम रखा गया। राजस्थान के पुष्कर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में कार्यक्रम में हार्वेस्ट कंपनी के सीईओ व फाउंडर भोपालगढ़ निवासी प्रिंस सैनी ने बतौर अतिथि शिरकत की। जहां उनका स्वागत किया गया। प्रिंस सैनी ने यहां आकर सबसे पहले अपने गुरुजी लखीदार का आशीर्वाद लिया और फिर महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की।
इस मौके पर हार्वेस्ट कंपनी के सीईओ व फाउंडर प्रिंस सैनी को अखिल भारतीय राजस्थान माली समाज का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रिंस सैनी ने कार्यक्रम में हाथोंहाथ 51 लाख रुपए नगद समाज को दान में दिए और आने वाले तीन महीने के अंदर समाज के भलाई कार्यों जैसे कि भवन निर्माण, स्कूल निर्माण, चिकित्सालय निर्माण इत्यादि के लिए दो करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

कोसी दियारा में कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी का दौरा, बाढ़ पीड़ितों की बदहाली देख भावुक हुए, प्रशासन पर उठाए सवाल

संवाद सूत्र, जागरण, मरौना (सुपौल): सुपौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी गुरुवार को कोसी दियारा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर वहां के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने घोघररिया पंचायत अंतर्गत खुखनहा, गोठ खुखनहा, लक्ष्मीनिया सहित लगभग एक दर्जन गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके की स्थिति का जायजा लिया।
दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने नेता को बताया कि कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। गांवों का संपर्क मुख्य भूमि से कट गया है, दैनिक जरूरतें पूरी करना दूभर हो गया है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि ने वहां पहुंचकर कोई राहत या व्यवस्था नहीं की है।
पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी प्रशासन सिर्फ कागजों पर बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार करता है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस मदद नहीं पहुंचती। विशेषकर नाव की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासन सिर्फ फॉर्मलिटी में नाव की व्यवस्था दिखाता है, जबकि हकीकत यह है कि लोग खुद अपने पैसे से नाव किराए पर लेकर काम चला रहे हैं।
इस मौके पर कांग्रेस नेता मिन्नत रहमानी ने कहा, "मैं आप सभी की समस्याओं को समझता हूं और जहां तक मेरे सामर्थ्य में होगा, हरसंभव सहायता करने का प्रयास करूंगा। साथ ही जिला प्रशासन से बात कर आपकी परेशानियों को उचित मंच तक पहुँचाने का काम करूंगा।" उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पहले भी जिला प्रशासन के आला अधिकारियों को इस क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया है, और अब पुनः उन्हें इस दिशा में सक्रियता दिखाने की याद दिलाएंगे।

मोदी सरकार खेल प्रतिभाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षक, मानसिक स्वास्थ्य सहायता

जयपुर, 24 जुलाई 2025। देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। मोदी सरकार की ओर से देश की खेल प्रतिभाओं को वित्तीय सहायता के साथ, प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सहायता तक प्रदान की जा रही है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए सतत रूप से प्रयासरत है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को सहायता मुहैया करवाई जा रही है। मोदी सरकार के खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, मेधावी खिलाडियों को पेंशन के लिए खेल निधि योजना, पंडित ?दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने सदन में यह जानकारी दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में चयनित खिलाड़ियों को मासिक आउट आफ पॉकेट भत्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, कोचिंग, फिजियोथेरेपी सहित व्यापक सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं खेलो इंडिया स्कीम में खेल प्रतिभाओं को पहचान, विकास, एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति और जमीनी स्तर पर कोचिंग सहायता प्रदान की जा रही है। इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम के तहत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मोदी सरकार की ओर से खेल करियर से संन्यास लेने के बाद खिलाड़ियों को आजीवन पेंशन की भी अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा तक प्रदान करने का प्रावधान किया गया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि खिलाड़ियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टीम और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर खेल मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक प्रशिक्षक तक नियुक्त किए गए है।

जागरूकता शिविर आयोजित

झुंझुनू। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के द्वारा संचालित पशु विज्ञान केंद्र, झुंझुनू द्वारा चूड़ी अजीतगढ़ में जागरुकता शिविर का आयोजन किया। केंद्र के प्रभारी
अधिकारी डॉ प्रमोद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान केन्द्र के डॉ उमेश कुमार ने विज्ञान विषय में केरियर संभावनाओं जैसे पशु चिकित्सक और 2 वर्षीय डिप्लोमा के स्कोप के बारे में विस्तारपूर्वक बताते हुए बैंक, आर्मी, पैरामिल्ट्री तथा प्राइवेट क्षैत्र

जैसे डेयरी मैनेजर, फार्मा कंपनियों में जॉब के अवसरों को विस्तारपूर्वक बताते हुए विभिन्न बीमारियों जैसे कोरोना, डेंगू, मलेरिया, रैबीज, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रूसेलोसिस आदि के साथ-साथ प्रोटोजोआ जनित बीमारियों के कारण, उपचार एवं बचाव के बारे में बताया।

शिक्षाविदों की दो दिवसीय वाकपीठ शुरू

झुंझुनू। जेजेटी विश्वविद्यालय में दो दिवसीय संस्था प्रधान वाकपीठ का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। जगदीश प्रसाद झाबरमल टीबड़ेवाला विश्वविद्यालय में मंडावा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक/उच्च माध्यमिक संस्था प्रधानों की दो दिवसीय वाकपीठ का आयोजन शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि हर्षिनी कुलहरी जिला प्रमुख झुंझुनू, अति विशिष्ट अतिथि एसडीएम मंडावा, मुनीश कुमारी, अध्यक्षता सीडीओ मंडावा अशोक कुमार शर्मा, विशिष्ट अतिथि सीडीईओ जयदीप झाझडि?ा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेश मील, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक संतोष सोई, सीबीईओ, चिड़ावा उमा दत्त झाझडि?ा, एडीईओ प्रमोद आबूसरिया, एसीईबीओ दामोदर प्रसाद जांगिड़, नवोदय विद्यालय काजड़ा प्रधानाचार्य रहे । इस अवसर पर अपने उद्बोधन में जिला प्रमुख हर्षिनी कुल्हरी ने नवाचारों के साथ शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालय में हैंडराइटिंग पर अलग से प्रयास करने का सुझाव दिया। साथ ही पौधरोपण कार्यक्रम में भी जोर शोर से शिक्षा विभाग के शामिल होने पर प्रकाश डाला।

पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को किया सम्मानित,पत्रकारिता समाज का दर्पण होती है- केबिनेट मंत्री खराड़ी

सुरज वर्मा
भीलवाड़ा 24 जुलाई
पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखने का कार्य नहीं, बल्कि यह समाज का दर्पण होती है, जो सत्य को उजागर करती है और बदलाव का वाहक बनती है. इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान समाचार एवं परिवार समाचार के सयुंक्त तत्वाधान मे राजसमंद स्थित जन संपर्क कार्यालय स्थित सभागार मे पत्रकार सम्मान समारोहै का आयोजन किया गया. इस समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया गया.सम्मानित होने वालों मे भीलवाड़ा से बृजेश शर्मा, महेंद्र नागौरी, व भेरू लाल माली इत्यादि पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने निडरता से समाज की समस्याओं को उजागर

किया और पत्रकारिता के उच्च मानकों को कायम रखाः कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के केबिनेट मंत्री, एवं जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबू लाल खराड़ी, व अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार विष्णु शर्मा ने की जनजाति विकास मंत्री खराड़ी ने
आज की पत्रकारिता के सामने चुनौतियाँ" विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि आज पत्रकारिता को सच बोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे सत्य का दामन न छोड़ें. इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य उन पत्रकारों को प्रोत्साहित करना था, जो निडरता से समाज की सच्चाई जनता तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं. समारोह के समापन पर सभी सम्मानित पत्रकारों को बधाई दी गई और उनके योगदान की सराहना की गई.इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता को प्रोत्साहन देना ही समाज के सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा

सडक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

झुंझुनू। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनू के तत्वावधान में क्वालिटी कंट्रोल सार्वजनिक निर्माण विभाग की एक्सईएन केसर जाटव के मुख्य आतिथ्य एवं सार्वजनिक निर्माण
विभाग सहायक अभियंता नितिक्षा वर्मा के नेतृत्व में सुरक्षित सडक मार्ग (सुसमा) कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीओ स्काउट महेश कालावत ने बताया कि इस अवसर पर क्वालिटी कंट्रोल की केशर

जाटव ने बताया कि सुरक्षित सडक मार्ग अभियान के अंतर्गत जिले भर के कॉलेज विद्यार्थियों एवं स्काउट गाइड्स, रोवर्स रेंजर्स को सडक सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत सुरक्षित सडक, सेंट्रल लाइन, सुचारू सुविधा युक्त सडक, सुंदर सडक, सडक सुरक्षा चिह्न, डिवाइडर, प्रॉपर पौधरोपण जैसी नॉर्म्स के अनुसार 7 किलोमीटर सडक को तैयार किया जाएगा एवं 10 सितंबर को जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उपस्थित स्काउट्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सडक सुरक्षा की विभिन्न जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर सीओ गाइड सुभीता महला ने सभी का आभार प्रकट किया तथा कार्यक्रम में स्काउट गाइड के शिक्षकों सहित विभिन्न विद्यालयों के 320 स्काउट्स एवं स्काउट प्रभारी रामदेव सिंह गढ़वाल, धर्मपाल सिंह, विक्की कुमार, अमरचंद, मान महेंद्र सिंह भाटी, विजेता कुमारी, मनोज कुमार, जीताराम, मुन्ना राजोरा, रतनलाल, हिम्मत सिंह, महेंद्र कुमार, जयपाल, बंसीलाल, कुलदीप सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने पिछले 3 साल में राष्ट्रीय लोक अदालतों में 23 करोड़ से अधिक मामलों का किया निस्तारण:– सांसद मदन राठौड़

जयपुर, 24 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया। प्राधिकरण की ओर से किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाए, इसकी समूचित व्यवस्था की जा रही है। मंत्रालय की ओर से पिछले तीन वर्षों में 23 करोड़ से अधिक मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया, वहीं करीबन 34 लाख राज्य लोक अदालत और 6 लाख 41 हजार

स्थायी लोक अदालतों में मामलों का निस्तारण कर लोगों को राहत प्रदान की गई। राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुनराम मेघवाल ने सदन में यह जानकारी दी।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राज्य, जिला और तहसील स्तर पर विधिक सहायता और परामर्श देकर जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मुहैया कराई जा रही है।
प्राधिकरणों द्वारा बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, एसटी–एससी और दिव्यांगजनों से संबंधित विविध विधियों एवं योजनाओं के प्रति देशव्यापी विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। पिछले तीन वर्षों में 13 लाख 83 हजार विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 14 करोड़ 96 लाख 72 हजार व्यक्ति उपस्थित होकर लाभान्वित हुए।
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्ष 2023–24 में विधिक सहायता प्रतिवादी काउंसल प्रणाली योजना का कार्यान्वयन भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। मंत्रालय की ओर से देशभर के 662 जिलों में विधिक सहायता प्रतिवादी काउंसलों के कार्यालय कार्यरत है। पिछले 2 वर्षों में 8 लाख 69 हजार मामले विधिक सहायता प्रतिवादी काउंसलों को सुपुर्द किए गए, इनमें से 5 लाख 85 हजार मामले निस्तारित किए गए।

जेजेटी की अदिति ने जर्मनी में शानदार प्रदर्शन कर भारत का परचम लहराया

झुंझुनू। जेजेटी यूनिवर्सिटी की प्रतिभाशाली छात्रा और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कुमारी अदिति भट्ट ने राइन-रुहर 2025 विश्व विश्वविद्यालय खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से भारत का गौरव बढ़ाया है। 22 से 26 जुलाई तक जर्मनी में आयोजित इस प्रतियोगिता में अदिति ने महिला एकल और युगल दोनों वर्गों में लगातार विजय हासिल की है और अब अगले दौर में पहुंच गई हैं। जानकारी देते हुए खेल निदेशक डॉ अरुण कुमार ने बताया कि 23 जुलाई को अदिति भट्ट ने अपने पहले मुकाबले में नीदरलैंड्स की डिएड ओडिज्क को 15-10, 15-7 से हराकर मजबूत शुरूआत की। 24 जुलाई को उन्होंने सिंगापुर की दानियल शरीफा को 15-6, 15-6 से पराजित कर अपनी बढ़त बरकरार रखी।
ये विजय उनके कौशल और दृढ़ संकल्प को दशार्ती हैं। अब अदिति एकल में प्री-क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इसके साथ ही महिला युगल में अदिति भट्ट और उनकी जोड़ीदार देविका सिहाग ने शानदार प्रदर्शन किया। 23 जुलाई को उन्होंने नेपाल की आयुष्मा नेपाल और निशम हंगमा सुब्बा की जोड़ी को 15-3, 15-0 से हराया।

तेजस्वी चौधरी को मिला स्वर्ण पदक

झुंझुनू। राजस्थान ताइक्वांडो द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता पीवी वर्ग अर्थात 8 वर्ष से कम उम्र के अंडर 30 भार वर्ग में तेजस्वी चौधरी ने स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। उक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 18 से 20 जुलाई को सरकारी स्टेडियम भरतपुर में संपन्न हुई, जिसमें झुंझुनू ने सामूहिक रूप से राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। झुंझुनू पहुंचने पर तेजस्वी चौधरी का शानदार सम्मान करते हुए परिजनों ने इस गोल्ड मेडल को विकास यात्रा के सफर में मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर तेजस्वी के नाना मूलचंद झाझडि?ा, शारदा देवी, प्रतिभा, संदीप गोदारा, प्रकृति, डॉ आदित्य झाझडि?ा, नितिन काजला, डॉ रामस्वरूप जाखड़, भारत सैनी, दीपक, विकास, आयुष, राजेश, विपिन, महेश चौधरी, योगी स्टेडियम झुंझुनू के कोच सुभाष योगी, संगीता योगी, टीम

कोच जगदीप बराला, मोहित ने इस स्वर्णिम जीत के लिए तेजस्वी चौधरी को बधाई व उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी।

पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित

झुंझुनू। भाजपा के हरियालो राजस्थान कार्यक्रम तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत झुंझुनू शहर की नेतराम मघराज टीबड़ेवाल गर्ल्स कॉलेज में भाजपा शहर मंडल संयोजक रवि गुप्ता के नेतृत्व में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर अभियान के झुंझुनू शहर मंडल संयोजक रवि गुप्ता, विजय कुमार सैनी, महेंद्र शर्मा, संदीप गोयल, पंकज रोहिल्ला, सौरभ जोशी, विद्याधर सैनी, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. राम कुमार सिंह, सुनीता कुमारी, अभिलाष आबुसरिया, कल्पना जानू, सुनीता थालोर, रोहिताश यादव, रघुराज सिंगोदिया, डॉ पूनम चावला, डॉ प्रीतम सिंह, राजवीर सिंह, शौर्य बुरी, सुरेंद्र कुमार, जगदीश कुमार, डॉ अनीता जैफ , डॉ सिद्धि जोशी, राजकुमार सहल, पुष्पेंद्र, राजपाल, समता, पूनम, आशीष गर्ग इत्यादि गणमान्य लोग मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल

जयपुर, 24 जुलाई। बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों का प्रसार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने एक अभिनव पहल की है। राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी को राज्य सरकार संविधान निमार्ता बाबा साहब के जीवन से जुड़े उन पांच ऐतिहासिक स्थलों- पंचतीर्थ की निःशुल्क रेल यात्रा कराएगी, जिनसे उनके महान व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह योजना ह्यवरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजनाह्न की तर्ज पर संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री श्री शर्मा का मानना है डॉ. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष और उनका संविधान निर्माण में अतुलनीय योगदान समाज के

लिए प्रेरणापुंज है। अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक और आत्मिक उत्थान की दिशा में बाबा साहब के विचार अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार की इस योजना से अनुसूचित जाति के यात्री बाबा साहब से जुड़े पांच स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। ये पंचतीर्थ सामाजिक सद्भाव, समानता और न्याय के सिद्धांतों की त्रिवेणी है, जो भारतीय जनमानस का मूल तत्व है।
यात्रा के साथ ही आवास और भोजन का व्यय भी वहन करेगी राज्य सरकार
इस योजना के अंतर्गत बाबा साहब की जन्मभूमि-महू (मध्यप्रदेश), दीक्षा भूमि-नागपुर (महाराष्ट्र), महापरिनिर्वाण भूमि-दिल्ली/अलीपुर, चैत्य भूमि-मुंबई, इंदू मिल-मुंबई (वर्तमान में स्मारक के रूप में विकसित) की यात्रा करायी जाएगी। इन सभी स्थलों तक यात्रियों को रेल मार्ग से पहुंचाया जाएगा।
यात्रा, आवास और भोजन का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।
प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के मूल निवासी कर सकेंगे आवेदन
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए तथा उसके पास जनआधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। साथ ही, आवेदक किसी संक्रामक रोग (जैसे कोविड, टीबी) से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आवेदन के साथ चिकित्सीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यात्रा के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं।
यात्रियों के चयन के लिए होगा समिति का गठन
योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। यदि आवेदन संख्या अधिक होती है तो यात्रियों का चयन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी या अन्य पारदर्शी माध्यम से किया जाएगा। चयन सूची और प्रतीक्षा सूची विभागीय वेबसाइट व सूचना पोर्टल पर जारी की जाएगी।

सहयोग एवं समन्वय की भावना से ही साकार होगी हरित जयपुर की संकल्पना

जयपुर, 24 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निदेर्शों की अनुपालना में मिशन हरियालो राजस्थान को सफल बनाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी जयपुर में मिशन के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित बैठक में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आयोजित होने वाले वन महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिला कलक्टर ने अधिकारियों को आगामी 27 जुलाई को हरियाली तीज के अवसर पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर जिले को आवंटित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को मिशन हरियालो राजस्थान के तहत होने वाले विशेष वृक्षारोपण के लिए समस्त आवश्यक तैयारियां समय से पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में जन प्रतिनिधियों, भामाशाहों, सामाजिक संगठनों, आद्योगिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केन्द्र, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एवं सोशल मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों, वन मित्रों के साथ-साथ आमजन की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

जिला भर में अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित करने हेतु नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों, वन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग सहित सभी विभागों को लक्षित स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक शासकीय कार्यालय परिसर, स्कूल, अस्पताल, चारागाह, सड़क किनारे एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरियालो राजस्थान अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि यह जनभागीदारी से जुड़ा एक जनांदोलन है, जिसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं इसलिए जन सहयोग एवं समन्वय से अभियान को सफल बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास सुनिश्चित किये जाएं।

पार्वती नदी में डूबे व्यक्ति का शव 6 घंटे की मशक्कत के बाद बरामद

देश का दर्पण न्यूज,धौलपुर (धर्मेन्द्र बिधौलिया) 24 जुलाई। धौलपुर कलेक्टरेट स्थित सिविल डिफेन्स कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पार्वती नदी सखवारा के पास एक व्यक्ति नदी में डूब गया है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक स्तर पर तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया। उपनियंत्रक एवं उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा के निर्देश पर नागरिक सुरक्षा दल को आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ मौके पर रवाना किया गया।

नागरिक सुरक्षा टीम और एसडीआरएफ ने चलाया अभियान घटनास्थल पर सिविल डिफेन्स टीम और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नागरिक सुरक्षा टीम के सदस्य ड्राइवर कोहिनूर, शिवकुमार शर्मा, विक्रम कुशवाह, प्रदीप वर्मा, रितेश कुमार और मनोज कुशवाह ने समर्पण और कुशलता के साथ लगातार 6 घंटे तक खोज अभियान चलाया।

मृतक की पहचान और कार्रवाई

लगातार प्रयासों के बाद दीनदयाल कुशवाह (उम्र 50 वर्ष) निवासी सत्तारपुरा मनिया का शव नदी से बाहर निकाला गया। शव को पुलिस थाना कौलारी को सुपुर्द किया गया।

नदबई थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया एसपी दिगंत आनंद ने

देश का दर्पण..दैनिक अखबार पत्रकार.= राकेश कोठेनिया हलेना

भरतपुर...जिले के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने गुरुवार को नदबई थाना पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर के मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष और रिकॉर्ड रूम समेत तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी ने साफ-सफाई, सुरक्षा प्रबंधन और रिकॉर्ड संधारण की स्थिति को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुरूप हों, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। निरीक्षण के बाद एसपी ने थाना स्टाफ के साथ बैठक कर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने गश्त को मजबूत करने, रात्रि गश्त नियमित रखने और जनसंपर्क बढ़ाने पर भी जोर दिया। मीडिया से बातचीत में दिगंत आनंद ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना, साइबर और संगठित अपराध पर नियंत्रण और जन शिकायतों का पारदर्शी निस्तारण रहेगा।

रायपुर : कृषि विज्ञान केन्द्र में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण

रायपुर/ब्यूरो। मशरूम का उत्पादन किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा साधन है।

इसे साल भर एक छोटे से कमरे के माध्यम में थोड़ा सा समय देकर आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि किसान विशेषकर महिला किसानों में मशरूम उत्पादन के प्रति विशेष रूचि देखी जाती है। इसी दृष्टि से कृषि विज्ञान केन्द्र, रायगढ़ में मशरूम उत्पादन पर एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

झाबुआ जिले की महिलाओं ने आपस में हाथ थाम दिया प्रकृति संरक्षण का सशक्त संदेश

इंदौर/ब्यूरो। इंदौर संभाग के झाबुआ जिले में कलेक्टर नेहा मीना की पहल पर महिलाओं की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लमातृधरा अभियान (नारी शक्ति से प्रकृति को शक्ति) अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मातृधरा अभियान के अंतर्गत नारीशक्ति से प्रकृति को शक्ति थीम के तहत महिलाओं ने गुरुवार को एक अद्वितीय और प्रभावशाली पहल करते हुए मानव आकृति और मानव श्रृंखला का निर्माण कर आपस में एक-दूसरे के हाथ में हाथ थाम कर प्रकृति संरक्षण का सशक्त संदेश दिया।

नारीशक्ति से प्रकृति को शक्ति थीम के अंतर्गत मातृधरा अभियान की एक प्रेरणादायक पहल में माँ त्रिपुरा कॉलेज झाबुआ की छात्राओं, प्राथमिक विद्यालय खांडियाखाल में शिक्षक एवं छात्रछात्राओं, महाशक्ति महिला मंडल राणापुर की महिलाओं, प्राथमिक विद्यालय लिमडी फलिया भूराडाबरा संकुल केंद्र माछलिया विकास खंड रामा की छात्रछात्राओं एवं श्री परशुरामेश्वर रामायण मंडल मेघनगर नाका की महिलाओं द्वारा मानव आकृति और मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इस रचनात्मक आयोजन का उद्देश्य प्रकृति संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता फैलाना तथा समाज में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करना था।

कार्यक्रम में महिलाओं ने मानवीय आकृति बनाकर यह दशार्या कि जैसे माँ सृजन और पालन की प्रतीक होती है, वैसे ही महिलाएँ प्रकृति की रक्षक और संवाहक भी हैं।

मानव श्रृंखला के माध्यम से उन्होंने एकजुटता, जागरूकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का संदेश पूरे समाज को दिया। विभिन्न महिला संगठन द्वारा संचालित इस अभियान में महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों और हरियाली के प्रतीक रंगों के साथ भाग लिया, जिससे दृश्य और भी प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन गया।

कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि मातृधरा अभियान प्रकृति और नारीशक्ति के गहरे संबंध को उजागर करता है। यह पहल समाज को यह सोचने पर विवश करती है कि प्रकृति की रक्षा में महिलाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस अभियान ने यह सिद्ध कर दिया कि जब महिलाएँ पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आती हैं, तो सामाजिक परिवर्तन की गति और भी तीव्र हो जाती है। मातृधरा अभियान आगे भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यह संदेश जन-जन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषकों के लिए आयोजित किया गया मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम

रायगढ/ब्यूरो।कृषि विज्ञान केन्द्र, रायगढ़ द्वारा कृषकों एवं कृषक महिलाओं के लिए मशरूम उत्पादन पर एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ.बी.एस. राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र ने कृषकों को बताया कि धान फसल के अवशेषों का उपयोग कर मशरूम उत्पादन एवं मशरूम बीज उत्पादन से कृषक अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मशरूम एक अत्यधिक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें कम लागत में अधिक मुनाफा अर्जित किया जा सकता है।

भोपाल: मलेरिया अधिकारी ने वायरोलॉजी लैब का निरीक्षण किया

भोपाल/ब्यूरो। जिला मलेरिया अधिकारी स्मृता नामदेव द्वारा गुरुवार को गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत संचालित स्टेट वायरोलॉजी लैब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने खान शाकिर अली गैस राहत अस्पताल का भी भ्रमण किया, जहाँ मलेरिया जांच, रिकॉर्ड संधारण और रिपोर्टिंग की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

डेंगू नियंत्रण की दिशा में मलेरिया कार्यालय की टीम द्वारा माह जुलाई में स्कूल हेल्थ एक्टिविटी के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें जोन-16 के ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल, जोन-9 के नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल तथा जोन-15 स्थित छात्रासाल हाई स्कूल शामिल हैं। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई तथा लार्वा सर्वेक्षण भी किया गया। टीम द्वारा अब तक 1780 घरों का लार्वा सर्वे किया गया एवं मलेरिया की 600 रक्त पट्टियाँ संधारित की गईं।

मंडला: जिले में प्रतिदिन लगेंगे राजस्व न्यायालय, पूरे दिन होगी सुनवाई

मंडला/ब्यूरो। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राजस्व न्यायालय प्रतिदिन लगाने का निर्णय लिया है। इसके परिपालन में मण्डला के सभी तहसीलदार न्यायालयों में अब दैनिक आधार पर पूरे दिन राजस्व प्रकरणों की सुनवाई होगी। जिले की सभी तहसीलों में इसके लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए जा चुके हैं। राजस्व न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करने वाले राजस्व अधिकारियों को गैर न्यायालयीन कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। इस प्रकार के गैर न्यायालयीन कार्यों जैसे प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर, भारतीय न्याय संहिता, अतिक्रमण तथा आवंटित थाना आदि कार्यों के लिए पृथक से राजस्व अधिकारियों को तैनात किया गया है।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने गुरुवार को यह जानकारी जिला योजना भवन में पत्रकार वार्ता में मीडिया संस्थान के प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने बताया कि नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत जिले में पदस्थ राजस्व अधिकारियों को इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश अनुसार अनुविभाग मण्डला की मण्डला तहसील में राजस्व न्यायालय के लिए प्र. तहसीलदार हिमांशु भलावी और बम्हनी तहसील के लिए नायाब तहसीलदार हीरालाल तिवारी को आदेशित किया गया है जबकि अनुविभाग मण्डला के गैर राजस्व न्यायालयीन कार्यों के लिए प्र. तहसीलदार पुष्पेन्द्र पन्द्रे को लगाया गया है।

इसी प्रकार नैनपुर अनुविभाग में हरीसिंह धुर्वे तहसीलदार नैनपुर एवं पूजा राणा नायब तहसीलदार चिरईडोंगरी न्यायालयीन कार्य में संबद्ध रहेंगे, जबकि अनुविभाग की दोनों तहसीलों के गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए कैलाश प्रसाद कौल उत्तरदायी होंगे।

नारायणगंज के लिए संगम पटले तहसीलदार नारायणगंज तथा चैनसिंह मार्को प्रभारी नायब तहसीलदार बीजाडांडी राजस्व न्यायालय के काम करेंगे, जबकि गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए आलोक सोनी प्रभारी नायब तहसीलदार बबलिया को जिम्मेदारी दी गई है। तहसील निवास के राजस्व के लिए संदीप नागोसे तहसीलदार निवास तथा गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए आलोक सोनी प्रभारी नायब तहसीलदार बबलिया को नियुक्त किया गया है।

घुघरी अनुविभाग के राजस्व न्यायालयों के लिए चंद्रकुमार वट्टे प्रभारी तहसीलदार घुघरी एवं धर्मेन्द्र साहू प्रभारी नायब तहसीलदार मोहगांव जबकि गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए इंद्रजीत सिंह सहायक अधीक्षक भू अभिलेख उत्तरदायी होंगे। इसी तरह बिछिया अनुविभाग के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के कार्यों में शंकरलाल मरावी प्रभारी तहसीलदार बिछिया, दिनेश वरकड़े नायब तहसीलदार मवई एवं अजय श्रीवास्तव प्रभारी नायब तहसीलदार अंजनिया संबद्ध किए गए हैं। गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए इंद्रजीत सिंह सहायक अधीक्षक भू अभिलेख मंडला को आदेशित किया गया है।

पत्रकार वार्ता के दौरान जिला योजना भवन में अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम सोनल सिडाम, तहसीलदार (राजस्व) हिमांशु भलावी, अतिरिक्त तहसीलदार पुष्पेन्द्र पन्द्रे सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

नशा बेचने वालों पर रहम, नशा करने वालों पर जुर्म शास्त्री नगर पुलिस का दोहरा मापदंड?

देश का दर्पण

जयपुर। शास्त्री नगर थाना पुलिस पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठे हैं। 23 जुलाई की सुबह 7 बजे पुलिस द्वारा चलाए गए एक कथित अभियान में तकरीबन 25 लोगों को थाने बुलाया गया। लेकिन यह कार्रवाई अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। थाने से जुड़ी शिकायतों के अनुसार, कांस्टेबल मामराज, प्रदीप, रोहताश और दिनेश ने न केवल आम लोगों के साथ बदसलूकी की, बल्कि महिलाओं के साथ भी मयार्दा की सारी सीमाएं लांघ दीं। आरोप है कि जिन घरों से लोगों को उठाया गया, वहां महिला कांस्टेबल मौजूद होते हुए भी पुरुष कांस्टेबलों ने महिलाओं से हाथापाई की और गाली-गलौज तक की। एक पीड़िता महिला ने बताया कि वह सुबह दूध लेने निकली थी, तभी पुलिसकर्मी उसे बिना कारण अपशब्द कहते हुए उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगे। महिला कांस्टेबल होते हुए भी उन्हें बुलाया नहीं गया, बल्कि कांस्टेबल रोहताश ने खुद महिला का हाथ पकड़ा। इसी दौरान शाहनवाज कुरैशी नाम के युवक को भी पुलिस थाने ले गई। परिजनों का आरोप है कि मामराज, प्रदीप, रोहताश और दिनेश ने थाने में बेरहमी से पीटा। हालत इतनी गंभीर हो गई कि रात को उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सीटी स्कैन और एमआरआई में शरीर पर मारपीट के गहरे निशान सामने आए हैं। शाहनवाज कुरैशी की हालत यह है कि वह अब खुद से उठने में भी असमर्थ है। अब सवाल यह है पुलिस पूछताछ के नाम पर आम लोगों को पीटेगी? महिलाओं से बदसलूकी करेगी? और सबसे अहम नशा बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं, लेकिन नशा करने वालों को जानवरों की तरह पीटना क्या यही है कानून का राज? स्थानीय लोगों में भारी रोष है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पुलिस की मारपीट से शाहनवाज के जीवन पर स्थायी असर पड़ेगा? और क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला दबा दिया जाएगा? अब निगाहें पुलिस के आला अधिकारियों पर टिकी हैं क्या वे इस बर्बरता पर कोई ठोस संज्ञान लेंगे या फिर शास्त्री नगर थाना फिर से अपनी मनमानी पर उतर आएगा?

PWD U PHED विभाग को अपनी जिम्मेदारी को निभाए परेशानी को जाने , कलेक्टर

देश का दर्पण. दैनिक अखबार पत्रकार .राकेश कोठेनिया हलेना

भरतपुर.. जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने गुरुवार को जल जीवन मिशन के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मिशन के चलते क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की शीघ्र मरम्मत की जाए, ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो।।कलेक्टर ने ACEO को विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराने और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में भौतिक सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाइप लाइन की लंबाई, गहराई और गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाए।

उन्होंने अभियंताओं को मासिक प्रगति रिपोर्ट का नियमित मूल्यांकन करने को कहा, ताकि समय रहते जरूरी सुधार हो सकें। विद्युत विभाग को जल जीवन मिशन और कृषि कनेक्शन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। साथ ही ढWD U PHED विभाग को आपसी समन्वय से काम को गति देने के निर्देश दिए गए।

भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक 26 व 27 जुलाई को नागपुर में

जबलपुर/ब्यूरो। भारतीय किसान संघ की अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जुलाई को अखिल भारतीय कार्यकारिणी की एक दिवसीय बैठक और उसके बाद 26 व 27 जुलाई को अखिल भारतीय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन संघ मुख्यालय स्मृति मंदिर परिसर, रेशिम बाग नागपुर में किया जा रहा है। जिसमें देश भर से भारतीय किसान संघ के 43 प्रांतों के पदाधिकारी शामिल होंगे।

नक्सलवाद की ढल रही रात, बस्तर में हो रही विकास की नई सुबह : मुख्यमंत्री साय

रायपुर/ब्यूरो। बस्तर रेंज में 2.54 करोड़ के इनामी 66 हार्डकोर नक्सलियों ने आज गुरुवार को आत्मसमर्पण किया है, इनमें 25 लाख के इनामी रेडट रामन्ना ईरपा उर्फ जगदीश जैसे शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, एक ही दिन में बीजापुर से 25, दंतेवाड़ा से 15, कांकेर से 13, नारायणपुर से 8 और सुकमा से 5 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। पिछले 18 महीनों में, हमारी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 1,570 माओवादी कैडर मुख्यधारा में लौट चुके हैं। यह हमारी सरकार की नीतियों के सकारात्मक प्रभाव और सुशासन का परिणाम है। यह इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि डबल इंजन सरकार के प्रयास केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हमने बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों के साथ-साथ सड़क, परिवहन, पेयजल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया है और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचा रहे हैं। "पूना मारगेम : पुनर्वास से पुनर्जीवन" की हमारी नीति बस्तर के उज्ज्वल भविष्य का संकल्प है। हम आत्मसमर्पण कर रहे नक्सलियों के भविष्य को संवारने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 4 जिलों में 2 करोड़ 27 लाख के इनामी 67 नक्सलियों ने

जगदलपुर/ब्यूरो। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक ही दिन में 67 नक्सलियों ने गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया। 02 करोड़ 27 लाख के इनामी इन 67 नक्सलियों ने यह आत्मसमर्पण बस्तर संभाग के चार जिलों में किया है। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का यह आत्मसमर्पण 'लाल आतंक' को अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है।

बस्तर संभाग में आज हरेली तिहार के अवसर पर 67 बड़े कैडर के नक्सलियों का यह आत्मसमर्पण सुरक्षाबलों के लिए बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इनमें कांकेर जिले में 13, नारायणपुर जिले में 8, सुकमा में 05, दंतेवाड़ा में 16 और बीजापुर में 25 नक्सलियों ने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 55 नक्सलियों पर कुल 2 करोड़ 27 लाख रुपये का इनाम घोषित है।

बीजापुर जिले में सरेंडर किए 25 नक्सलियों में से 23 पर 01 करोड़ 15 लाख रुपये का इनाम घोषित था। इसमें एक एसजेडसीएम कैडर का नक्सली शामिल है। बस्तर में पहली बार एसजेडसीएम कैडर के 25 लाख के इनामी नक्सली रमन्ना इरपा ने हथियार डाले हैं। कांकेर में 13 नक्सलियों पर 62 लाख रुपये का इनाम घोषित था। नारायणपुर में आत्मसमर्पण किए 8 नक्सलियों पर 33 लाख रुपये का इनाम घोषित था। वहीं दंतेवाड़ा में 16 नक्सलियों में से 5 पर 17 लाख रुपये का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से मिलिट्री कंपनी नंबर 01 का कमांडर से लेकर डीवीसीएम, पीपीसीएम और एसीएम कैडर के नक्सली शामिल हैं।

कांकेर जिले में 13 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट, परतापुर और माड़ डिवीजन में सक्रिय नक्सली शामिल हैं। इनमें 01 नक्सली पर 10 लाख रुपये, 4 नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपये, 3 पर 5-5 लाख रुपये और 5 पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। 10 लाख रुपये का इनामी हार्डकोर नक्सली मिलिट्री कंपनी नंबर 01 का कमांडर मंगलू उर्फ रूपेश शामिल है।

बीजापुर जिले में 25 लाख रुपये के इनामी नक्सली रमन्ना इरपा ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। पहली बार स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर कैडर के नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा 8-8 लाख रुपये के 5 नक्सली, 5-5 लाख रुपये के 8 नक्सली, 2 लाख रुपये के 1 और 1-1 लाख रुपये के 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें डीवीसीएम, पीपीसीएम और एसीएम कैडर के नक्सली शामिल हैं।

नारायणपुर जिले में भी कुल 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 8 लाख रुपये के 3 नक्सली, 5 लाख रुपये का 1 और 1-1 लाख रुपये के 4 नक्सली शामिल हैं।

फ्रिज में सब्जियों को थैलियों में करती हैं स्टोर, जान लें ये आदत कैसे बन जाती है जानलेवा

आज कल खाने-पीने की चीजों में प्लास्टिक का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है. चाहे फिर वो टी बैग्स हो, मार्केट वाला सैंडविच हो या फिर पैक्ड फूड. कुछ लोग इन्हें ऐसे ही फ्रिज में स्टोर भी कर लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हमारे सेहत पर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है. इसको लेकर एक रिसर्च भी सामने आई है. चलिए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं.

भारतीय घरों में अक्सर महिलाएं सब्जियां खरीदकर उन्हें ऐसे ही प्लासिटक की थैलियों में ही फ्रिज में स्टोर कर लेती हैं. ये आदत आम है लेकिन कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है. हाल ही में एक स्टडी में में खुलासा हुआ है कि प्लास्टिक की थैलियां में रखी चीजें कैसे आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं.आज कल आपको ज्यादातर खाने -पीने की चीजें प्लास्टिक बैग्स या कंटेनर में ही मिलती है. उन्हें फिर वैसे ही फ्रिज में स्टोर भी कर लिया जाता है. फिर चाहे वो बाहर से लाया सैंडविच हो या फिर पैक्ड फूड. लेकिन रोजाना की ये आम आदतें आपके सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं चलिए जानते हैं?क्या कहती है रिसर्च ?ह्वक्क्ष् साइंस ऑफ फूड जर्नल में छपे एक अध्ययन में बताया गया है कि, कैसे कांच और प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन को बार-बार खोलने और बंद करने से उनमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक कण निकलते हैं और हमारी ड्रिंक्स में घुल जाते हैं.खाने -पीने की चीजों रिसर्च करने वाली संस्था फूड पैकेजिंग फोरम की साइंटफिक कम्युनिकेशन ऑफिसर बताती हैं कि, ÷रिसर्च से पता चला है कि बोतल खोलने के हर एक प्रयास के साथ माइक्रोप्लास्टिक्स की संख्या बढ़ती जाती है. यानी आप जितनी बार बोतल खोलेंगे माइक्रो और नैनोप्लास्टिक्स रिलीज होंगे. अध्ययन के अनुसार, अब तक बीयर, कैन्ड फिश, चावल, मिनरल वॉटर, टी बैग्स, टेबल सॉल्ट, टेकअवे फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे फूड्स और ड्रिंक्स में माइक्रो और नैनोप्लास्टिक कण पाए जा चुके हैं.

क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक्स?

सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स होता क्या है. दरअसल, ये प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण होते हैं, जो दिखाई भी नहीं देते हैं. प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं. कभी-कभी इनका साइज थोड़ा बड़ा भी हो सकता है.वैज्ञानिकों के मुताबिक, ये आपको प्लास्टिक की हर चीज में मिल जाएंगे और अब तो ये हमारे खाने-पीने की चीजों में भी पहुंच चुके हैं. हाल ही में आई रिसर्च में इस बात का खुलासा भी हुआ है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स अब हमारे खाने को दूषित कर रहा है, जिससे सेहत को भी बुरा असर पड़ रहा है.

प्लास्टिक बैग्स में फूड रखना कितना जानलेवा?

आज कल आपको अमूमन चीजें चाहे फिर खाना, पीना हो या फिर बर्तन, में प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है. ऐसे में माइक्रोप्लास्टिक हमारे खाने, पीने से लेकर किचन में भी तेजी से घुल रहा है, जिसका असर हमारे सेहत पर भी पड़ रहा है. ये कण इतने छोटे होते हैं की व्यक्ति के टिशूज में अब्जॉर्ब हो सकते हैं और खून के जरिए पूरे शरीर में फैल सकते हैं. रिसर्च में दावा किया गया है कि 96त्न तक चेक किए गए पैकेजिंग फूड में माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है.

माइक्रोप्लास्टिक का शरीर पर पड़ रहा बुरा असर

हाल की रिसर्च में पाया गया है कि, माइक्रोप्लास्टिक अब लोगों के खून, फेफड़ों और दिमाग तक में फैल रहे हैं. आपको जान कर हैरानी होगी की एक अध्ययन में पाया गया कि, 80त्न लोगों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मिला है. यानी की अब ज्यादातर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं.

दुनिया की लाखों जिन्दगियां में जहर घोलता अकेलापन

अकेलापन केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक विफलता का संकेत है। जब हम तकनीक, दौड़ और स्वार्थ में इतने उलझ जाते हैं कि किसी के पास ÷सुनने का समय÷ नहीं रहता, तब अकेलापन जन्म लेता है।

हर छठा व्यक्ति अकेला है'-यह निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की ताज़ा रिपोर्ट का है, जिसने पूरी दुनिया को चिन्ता में डाला है एवं सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम कैसी समाज-संरचना कर रहे हैं, जो इंसान को अकेला बना रही है। निश्चित ही बढ़ता अकेलापन कोई साधारण सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है, जो व्यक्तियों, समाजों, और व्यावसायिक संस्थानों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। दुनिया के करोड़ों लोग टूटे रिश्तों व संवादहीनता की स्थितियों में नितांत खामोशी का जीवन जी रहे हैं। गौर करे तो इंसान के भीतर की ये खामोशी लाखों जिंदगियां में महामारी के रूप में जहर घोल रही है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे ज्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। वृद्ध तो पहले से ही सामाजिक एवं पारिवारिक विसंगतियों में उपेक्षित है। निश्चय ही जीवन की विसंगतियां एवं विषमताएं बढ़ी हैं। कई तरह की चुनौतियां सामने हैं। पीढ़ियों के बीच का अंतराल विज्ञान व तकनीक के विस्तार के साथ तेज हुआ है।डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया की लगभग 16 प्रतिशत आबादी आज किसी न किसी रूप में अकेलेपन, सामाजिक अलगाव या भावनात्मक दूरी का शिकार है। यह स्थिति केवल वृद्धजनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं, कामकाजी पेशेवरों, और यहां तक कि बच्चों तक फैल चुकी है। डिजिटल युग में जहां सब कुछ 'कनेक्टेड' लगता है, वहीं इंसानी रिश्तों में एक अदृश्य दूरी, कृत्रिमता और आत्मीयता का अभाव देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में हम जितने अधिक जुड़े हैं, उतने ही भावनात्मक रूप से अकेले हो गए हैं। व्यक्तिवादी सोच, सामाजिक दुष्प्रभाव एवं रिश्तों की बिखरती दीवारों में अकेलेपन का घातक प्रभाव सामाजिक ढांचे पर गहरे रूप में पड़ रहा है। पारिवारिक संबंधों में दरारें, विवाहों में असंतोष, और तलाक की बढ़ती दरें इसकी साफ़ निशानी हैं। युवा पीढ़ी में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति और नशे की ओर झुकाव एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया है। बुजुर्गों में अकेलेपन से उत्पन्न अल्ज़ाइमर, डिमेंशिया और अन्य मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं।

अकेलापन केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक विफलता का संकेत है। जब हम तकनीक, दौड़ और स्वार्थ में इतने उलझ जाते हैं कि किसी के पास ÷सुनने का समय÷ नहीं रहता, तब अकेलापन जन्म लेता है। अब समय आ गया है कि हम फिर से रिश्तों, संवाद और करुणा की दुनिया की ओर लौटें। अन्यथा अकेलापन, उदासी और असंतुष्टि की भावनाएं कचोटती रहेगी। मानो खुद के होने का एहसास, कोई इच्छा ही ना बची हो। तब छोटी-छोटी चीजों में छिपी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से लोग जिंदा हैं, पर जीवित होने के जादुई एहसास को कम ही छू पाते हैं। सोच के भौतिकवादी एवं सुविधावादी होने से हमारी आकांक्षाओं का आसमान ऊंचा हुआ है। लेकिन यथार्थ से साम्य न बैठा पाने से कुंठा, हताशा व अवसाद का विस्तार हो रहा है। जिसके चलते निराशा हमें एकाकीपन या अकेले होने की ओर धकेल देती है। निश्चित ही सोशल मीडिया का क्रांतिकारी ढंग से विस्तार हो रहा है। लेकिन इसकी हकीकत आभासी है, कृत्रिम है, दिखावटी है। हर कोई सोशल मीडिया मंचों पर हजारों मित्र होने का दावा करता है, लेकिन ये मित्र कितने संवेदनशील है? कितने करीब है? इन प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही है, यथार्थ के जीवन में व्यक्ति बिल्कुल अकेला एवं गुमशुम होता है। आभासी मित्रों का कृत्रिम संवाद हमारी जिंदगी के सवालों का समाधान नहीं दे सकता, अकेलापन दूर नहीं कर सकता। निश्चित रूप से कृत्रिम रिश्ते हमारे वास्तविक रिश्तों के ताने-बाने को मजबूत नहीं कर सकते।विडंबना यह है कि कृत्रिमताओं के चलते कहीं न कहीं हमारे शब्दों की प्रभावशीलता में भी कमी आई है। जिससे व्यक्ति लगातार एकाकी जीवन की ओर उन्मुख होना लगा है। हमारे संयुक्त परिवारों का बदलता स्वरूप एवं एकल परिवारों का बढ़ता प्रचलन भी इसके मूल में है। पहले घर के बड़े बुजुर्ग किसी झटके या दबाव को सहजता से झेल जाते थे। सब मिल-जुलकर आर्थिक व सामाजिक संकटों का मुकाबला कर लेते थे। लेकिन अब बुजुर्ग एकाकीपन एवं अकेलापन से जूझ रहे है। केरल में इसी तरह के वृद्ध-संकट को महसूस करते हुए वहां की सरकार ने वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया है, जो एक सूझबूझभरा कदम है। आज वृद्धों को अकेलापन, परिवार के सदस्यों द्वारा उपेक्षा, दुर्व्यवहार, तिरस्कार, कटुक्तियां, घर से निकाले जाने का भय या एक छत की तलाश में इधर-उधर भटकने का गम हरदम सालता रहता। वृद्ध समाज इतना कुंठित, अकेला एवं उपेक्षित क्यों है, एक अहम प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज-निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उन्हें वृद्धों को अकेलेपन को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू करना चाहिए, ताकि वृद्धों की प्रतिभा, कौशल एवं अनुभवों का नये भारत-सशक्त भारत के निर्माण में समुचित उपयोग हो सके एवं आजादी के अमृतकाल में अकेलापन एक त्रासदी न बन सके।कामकाजी परिस्थितियों का लगातार जटिल होना एवं महंगी होती जीवनशैली ने अकेलापन के संकट को गहरा बनाया है। उन परिवारों में यह स्थिति और जटिल है, जहां पति-पत्नी दोनों कामकाजी हैं और बच्चे हॉस्टलों व बोर्डिंग स्कूल में रह रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम का बोझ इंसानों को अकेला बना रहा है। कार्यालयों और कार्यस्थलों पर भी अकेलापन एक गंभीर चुनौती बन रहा है। कर्मचारी भावनात्मक जुड़ाव की कमी के कारण कार्य में रुचि नहीं लेते। टीम वर्क, इनोवेशन और सहयोग पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। अकेलापन लंबे समय तक बना रहा तो यह बर्नआउट, कार्य से असंतोष और कर्मचारी त्यागपत्र जैसी स्थितियों को जन्म देता है। इससे उत्पादकता में भी गिरावट आती है। मेकिन्से और डेलॉइट जैसी वैश्विक कंसल्टिंग फर्म्स की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि अकेलापन कर्मचारियों की उत्पादकता को 15-20 प्रतिशत तक घटा सकता है, जिससे कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अकेलेपन के इस संकट से निपटने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर सामूहिक प्रयास ज़रूरी हैं। परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ समय बिताना ही असली 'समृद्धि' है। कंपनियों और संस्थानों में कर्मचारियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझने वाला नेतृत्व चाहिए। डिजिटल संवाद की जगह आमने-सामने संवाद, 'वर्क फ्रॉम होम' की जगह 'वर्क विद कम्युनिटी' को प्राथमिकता देनी होगी। ऑफिसों और समाज में काउंसलिंग, समूह चर्चा, मेडिटेशन, और योग को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकारों को अकेलेपन को एक जनस्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देनी चाहिए और सामाजिक समावेश के लिए ठोस कार्यक्रम चलाने चाहिए।

डब्ल्यूएचओ का वह आंकड़ा भी चौंकाता है कि अकेलापन हर साल तकरीबन आठ लाख लोगों की जीवन लीला समाप्त कर रहा है। जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति न केवल समाज व अपने कार्यालयी परिवेश से अलग-थलग हुआ है, बल्कि वह परिवार से भी कटा है। पिछले दिनों देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने कार्यालयों में काम के घंटे बढ़ाने का आग्रह किया था। एक उद्यमी ने तो यहां तक कहा कि क्या जरूरी है कि घर में रहकर पत्नी का ही चेहरा देखा जाए। यह एक संवेदनहीन एवं बेहूदा प्रतिक्रिया थी। दरअसल, लोगों में यह आम धारणा बलवती हुई है कि जिसके पास पैसा है तो वह सबकुछ कर सकता है। जिसके चलते उसने आस-पड़ोस से लेकर कार्यस्थल पर सीमित पहुंच बनायी है। यही वजह है कि हमारे इर्द-गिर्द की भीड़ और ऑनलाइन जिंदगी के हजारों मित्रों के बावजूद व्यक्ति अकेलेपन को जीने के लिये अभिशप्त है। सही बात ये है कि लोग किसी के कष्ट और मन की पीड़ा के प्रति संवेदनशील व्यवहार नहीं करते। हर तरफ कृत्रिमताओं का बोलबाला है। हमारे मिलने-जुलने वाले त्योहार भी अब दिखावे व कृत्रिम सौगातों की भेंट चढ़ गए हैं। हमें उन कारकों पर मंथन करना होगा, जिनके चलते व्यक्ति निजी जीवन में लगातार अकेला या एकाकी होता जा रहा है। असल में अकेलापन तभी मिटेगा जब हम फिर से इंसान बनेंगे-संवेदनशील, सजीव, संवाद और रिश्तों की गर्माहटत से भरे हुए।

संपादकीय

अविश्वास की रिकॉर्डिंग

संक्रमणकाल से गुजर रहे भारतीय समाज में पति-पत्नी के दरकते रिश्ते समाजविज्ञानियों के लिए चिंता का विषय हैं। आये दिन विभिन्न अदालतों में ऐसे मामलों से जुड़े विवाद मीडिया की सुर्खियां बनते रहते हैं। निस्संदेह, भारतीय समाज में पहले ऐसे मामले कम ही नजर आते थे और विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा जाता रहा है। यहां तक कि हिंदू विमर्श में तलाक शब्द का कोई सटीक पर्यायवाची भी नहीं मिलता। लेकिन इधर रिश्तों में लगातार बढ़ता अविश्वास, अलगाव व विवाद वर्तमान समय की हकीकत है। बल्कि पिछले दिनों एक न्यायाधीश को यहां तक कहना पड़ा कि वैवाहिक विवादों के बोझ से न्यायिक प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। इसी क्रम में पिछले दिनों पति-पत्नी के विवाद में गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल को साक्ष्य मानने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि पति या पत्नी द्वारा गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत अब एक सबूत के तौर पर स्वीकार होगी। शीर्ष अदालत का कहना था कि इस तरह की रिकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट में एक अहम सबूत के तौर पर स्वीकार की जा सकती है। दरअसल, इस बाबत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को ही रद्द कर दिया। दरअसल, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का इस बाबत मानना था कि किसी पक्ष की जानकारी के बिना उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना उसकी निजता का उल्लंघन होगा। उच्च न्यायालय का तर्क था कि इस रिकॉर्डिंग को फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय का कहना था कि आमतौर पर पति-पत्नी सामान्य तौर पर या आवेश में खुलकर बात करते हैं। उन्हें इस बात का भान नहीं होता कि कहीं उनकी बात रिकॉर्ड हो रही है या उनकी बातचीत भविष्य में अदालत में साक्ष्य की तौर पर पेश की जा सकती है।

अपने तर्क के समर्थन में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ न्यायिक फैसलों का भी जिक्र किया था। खासकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पति-पत्नी की सहमति के बिना बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है। साथ ही गैर-कानूनी भी है। इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने उन दलीलों को अस्वीकार्य किया कि जिसमें कहा गया था कि इस तरह के साक्ष्य की अनुमति देने से घरेलू सौहार्द व वैवाहिक रिश्तों पर आंच आएगी। यह भी कि इससे समाज में पति-पत्नी की जासूसी की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साक्ष्य अधिनियम का भी अतिक्रमण होगा। शीर्ष अदालत की पीठ का इस बाबत कहना था कि अदालत में पहुंचे रिश्ते इस बात का पर्याय हैं कि दोनों के रिश्ते सहज व सामान्य नहीं हैं। जाहिरा तौर पर रिश्तों में अविश्वास के चलते ही वैवाहिक मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं। उल्लेखनीय है कि बठिंडा की एक परिवार अदालत ने पत्नी की क्रूरता साबित करने वाली फोन रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दी थी। जिसे पत्नी ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी दलील थी कि यह रिकॉर्डिंग उसके संज्ञान में लाए बिना की गई थी। जिससे उसके निजता के मूल अधिकार का हनन होता है। जिस पर उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया, साथ ही फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि बातचीत एक पक्ष ने गोपनीय ढंग से रिकॉर्ड की है, अत- इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भी कहा कि तय करना कठिन है कि ये बातचीत किन परिस्थितियों व भावनात्मक आवेश के चलते हुई थी। ऐसे में आरोपों की तार्किकता सिद्ध करना कठिन है। साथ ही बहुत संभव है कि रिकॉर्ड करने वाले पक्ष ने सतर्क होकर प्रतिक्रिया दी हो। ऐसे में उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं हो सकती।

सर्वाधिक कटुतापूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा बिहार

सर्वाधिक कटुतापूर्ण विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा बिहार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली समेत कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है। 1 अगस्त से बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। ये योजनाएं न केवल राजनीतिक रणनीतियां हैं, बल्कि मतदाताओं के रूझान में संभावित बदलाव लाने वाली भी हैं।इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बिहार में राजनीति गरमा रही है। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल इसकी तैयारी में जुटे हैं और आखिरी क्षणों में किसी भी तरह की अड़चन से बचने के लिए सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी है। यह चुनाव जीत के लिए एक कड़ा मुकाबला होगा।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली समेत कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की है। 1 अगस्त से बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। ये योजनाएं न केवल राजनीतिक रणनीतियां हैं, बल्कि मतदाताओं के रूझान में संभावित बदलाव लाने वाली भी हैं।राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी चुनाव जीतने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया है, साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त बिजली देने की आलोचना की है।बिहार की राजनीति में तीन मुख्य दलों का दबदबा है- राष्ट्रीय जनता दल (राजद), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू), जिनके अपने-अपने वफादार मतदाता हैं। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दल शामिल हैं, जिसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं।2020 के नतीजों से पता चलता है कि राजद 23.11प्रतिशत वोट शेयर हासिल कर सभी दलों से आगे था। भाजपा 19.4 प्रतिशत वोट के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसकी गठबंधन सहयोगी जद (यू) 15.39 प्रतिशत वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को केवल 9.4 प्रतिशत और वामपंथी दलों को 4.64 प्रतिशत वोट मिले।राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का लक्ष्य कुशवाहा, धानुक और मल्लाह सहित अन्य जातियों तक पहुंच बनाकर अपने मुस्लिम और यादव मतदाता आधार का विस्तार करना है। राजद गैर-पासवान और गैर-मांझी दलित मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के साथ सहयोग कर रही है।सत्ता विरोधी लहर के कारण, एनडीए को 2025 के चुनाव में 2020 की तुलना में अधिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता काफ़ी कम कर चुके हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझ रहे हैं।भाकपा (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन का लक्ष्य इंडिया गठबंधन के भीतर हाशिए पर पड़े मज़दूर वर्ग के मतदाताओं का समर्थन करना है। साथ ही, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी युवा, जाति-निरपेक्ष मतदाताओं को लक्षित करती है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को चुनौती देने के लिए नई पार्टियां भी उभर रही हैं।अपने चुनावी वायदों को जारी रखते हुए, नीतीश कुमार छतों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।16 जुलाई को, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों के रिक्त पदों की पहचान करने और 1,20,000 से अधिक इच्छुक शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-4 में तेजी लाने का निर्देश दिया। 8 जुलाई को, नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों और स्थायी निवासियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत कोटा लागू किया, जिससे लैंगिक समानता और महिलाओं के लिए कार्यबल के अवसरों को बढ़ावा मिला।

नौकरियां मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा हैं। बिहार मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियां सृजित करने की योजना को मंजूरी दी है, और राज्य के उज्जवल भविष्य का वायदा किया गया है।नीतीश कुमार ने एक्स पर घोषणा की, %मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे राज्य में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, तथा लगभग 39 लाख को रोज़गार मिला है। हमारा लक्ष्य 50 लाख से ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा करना है। सात निश्चय कार्यक्रम के माध्यम से, हम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वालों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, और हम अगले पांच वर्षों में इन प्रयासों का विस्तार करने की योजना बना रहे है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना को अपराध की राजधानी% करार दिया। बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर कहा कि %एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता का ध्यान भटकाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस कदम की आलोचना की।

नीतीश इन लाभों की घोषणा क्यों कर रहे हैं? 2025 के चुनाव बिहार में कांटे की टक्कर वाले होने की उम्मीद है, और 20 साल से ज़्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार दसवीं बार सत्ता में आने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। यह चुनाव बिहार में उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। एक ओर, यह स्थिति नीतीश के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है; तो दूसरी ओर, सत्ता में उनके 20 साल मतदाताओं को काफ़ी निराश कर सकते हैं। उनका समर्थन कर रही भाजपा नीतीश को एनडीए के नेता के रूप में पेश कर रही है। 2020 के चुनावों में, जदयू को केवल 43 सीटें मिलीं, जबकि भाजपा को 74 सीटें मिलीं, जिसके कारण नीतीश को मुख्यमंत्री पद देने का फ़ैसला किया गया।नीतीश को बिगड़ती कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, ख़ासकर शराबबंदी के खराब क्रियान्वयन और शिक्षा के निम्न स्तर के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शिक्षकों के रिक्त पद और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों ने नीतीश की लोकप्रियता को प्रभावित किया है।

74 साल की उम्र में भी, नीतीश कुमार अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों और जेडी(यू) के खराब प्रदर्शन के बावजूद, बिहार की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बने हुए हैं। उन्हें महादलितों, कुर्मियों, कोइरियों और अन्य पिछड़े वर्गों का मज़बूत समर्थन प्राप्त है। जेडी(यू) को भाजपा के साथ गठबंधन करने पर उच्च जातियों और गैर-यादव ओबीसी का समर्थन मिलता है, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने पर उसे उच्च जातियों का समर्थन नहीं मिलता, जैसा कि 2014 के चुनावों में देखा गया था।

विपक्ष राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तरह बिहार चुनावों में भी भाजपा द्वारा वोटों की लूट की चेतावनी दी है। चुनाव से तीन महीने पहले ही राजनीतिक पारा गरमा गया है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक, दोनों ने बिहार चुनावों को खास महत्व दिया है। नौ बार मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का भविष्य भी दांव पर है।

डिजिटलीकरण से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में आया उछाल

एजेंसी
नई दिल्ली। नये ई-फाइलिंग पोर्टल की शुरुआत से पिछले चार साल में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 36 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या वित्त वर्ष 2020-21 के 6.72 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 9.19 करोड़ पर पहुंच गयी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गुरुवार को राष्ट्रीय आयकर दिवस पर लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आयकर देश के आर्थिक तानेबाने की रीढ़ है। यह विकास परियोजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण को शक्ति प्रदान करता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में वृद्धि, जीएसटी और अन्य माध्यमों से ट्रैकिंग बढ़ाने के कारण आयकर संग्रह भी उसी तेजी से बढ़ा है। पिछले चार साल में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह दोगुने से भी अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 12.31 लाख करोड़ रुपये था जो 2024-25 में 27.02 लाख करोड़ रुपये हो गया है। मौजूदा सरकार ने पिछले 11 साल में कर आधार बढ़ाकर कर संग्रह बढ़ाने का प्रयास किया है और डिजिटलीकरण इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। भारत में कर प्रणाली का इतिहास काफी पुराना है। कई शासकों ने अपने तरीके से कर लगाये, लेकिन मौजूदा कर प्रणाली की शुरुआत 24 जुलाई 1860 को हुई जब सर जेम्स विल्सन ने आयकर की अवधारणा को लागू किया।

बिजली क्षेत्र में 10 साल में 65 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत : रिपोर्ट

नई दिल्ली। देश में बिजली की मांग अगले 10 वर्षों में बढ़कर चार ट्रिलियन यूनिट पहुँच जायेगी जिसे पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में 65 से 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। ओमनीसाइंस कैपिटल द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में साल 2035 तक 1,300 से 1,400 गीगावाट अतिरिक्त बिजली क्षमता स्थापित किये जाने की संभावना है। इसके लिए 65 से 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी। इसमें पारेषण ग्रिडों और स्मार्ट मीटर लगाने पर करीब 15 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे।ओमनीसाइंस कैपिटल के अध्यक्ष और मुख्य पोर्टफोलियो मैनेजर अश्विनी शामी ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ते झुकाव को देखते हुए बुनियादी ढाँचे में 65 लाख करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा अवसर है। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा समय में देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 475 गीगावाट है जिसमें 220 गीगावाट यानी 46 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा है। साल 2035 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 1,364 गीगावाट होने की संभावना है जिसमें 971 (71 प्रतिशत) गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा होगी।

वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक भारत मंडपम में

नई दिल्ली । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 25 से 28 सितंबर तक राजधानी के मंडपम में 'वर्ल्ड फूड इंडिया' के चौथे संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को यहां विशेष कार्यक्रम में इस विशाल आयोजन के लिए प्रचार ब्रोशर, वेबसाइट और ऐप का अनावरण किया। श्री पासवान ने जोर दिया कि वर्ल्ड फूड इंडिया महज एक व्यापार मेला नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी मंच है जिसका उद्देश्य भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया का चौथा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 90 से ज्यादा देशों, 2,000 से ज्यादा प्रदर्शकों और खेत से लेकर खाने तक की पूरी खाद्य मूल्य श्रृंखला से जुड़े हज़ारों हितधारकों के शामिल होने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव अविनाश जोशी ने सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान और दूध, बाजरा तथा दालों के प्रसंस्करण में इसके नेतृत्व पर प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हानिकारक प्रभाव के उपचार के लिए संगठित हों छोटी, मझोली फर्म : वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली। देश की छोटी फर्मों को वैश्विक व्यापार में उनके सामूहिक हितों पर किसी अनुचित व्यवहार के कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव के निराकरण के लिए वाणिज्य विभाग की ओर से उन्हें संगठित होने का सुझाव दिया गया है। विभाग के व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक सिद्धार्थ महाजन ने राजधानी में 'व्यापार उपचार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईएस): निष्पक्ष व्यापार हेतु क्षमता निर्माण' विषय पर पिछले दिनों हुई एक तकनीकी कार्यशाला में यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि व्यापार उपचार कार्यवाहियों में अपने सामूहिक हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए छोटी फर्मों के एकजुट होने और संघ बनाने की बड़ी जरूरत है। कार्यशाला का आयोजन व्यापार और निवेश विधि केंद्र (सीटीआईएल), भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), वाणिज्य विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) को उपलब्ध व्यापार उपचार व्यवस्थाओं के प्रति संवेदनशील बनाकर और इन प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना था।

सर्राफा बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुख, सोना और चांदी नए शिखर पर पहुंचे

एजेंसी
नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी का रुख बना हुआ है। सोना आज 950 रुपये से लेकर 1,040 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज 900 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी दर्ज की गई है। कीमत में उछाल आने के कारण आज देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 1,02,340 रुपये से लेकर 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 93,810 रुपये से लेकर 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,19,000 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना आज

1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,02,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,02,390 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 93,860 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,02,340 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 93,810 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,02,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,02,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 93,860 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,02,490 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 93,960 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के सर्राफा बाजार में भी आज सोना महंगा हुआ है।

रुपये में गिरावट जारी, 3.25 पैसे टूटा

एजेंसी
मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर की माँग आने से अमेरिकी मुद्रा की तुलना में रुपया 3.25 पैसे टूट गया। कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 86.4125 रुपये का बोला गया। भारतीय मुद्रा लगातार छठे कारोबार दिवस पर कमजोर हुई है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की अनुसंधान विश्लेषक रिया सिंह ने बताया कि रुपया 86.50 रुपये प्रति डॉलर की तरफ बढ़ रहा है जो चार सप्ताह का निचला स्तर है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में हो रही देरी से बाजार में निवेशक आशंकित हैं। विशेषकर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद उनकी चिंता और बढ़ गयी है जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों के खिलाफ ऊंचे आयात शुल्क लगाने की बात कही थी। रुपया आज 8.50 पैसे की गिरावट के 86.4650 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और यही इसका दिन का

निचला स्तर रहा। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लिवाली से सुबह के समय यह 86.3450 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ, लेकिन बाजार में डॉलर की माँग निकलने से फिर दबाव में आ गया।दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में रही तेजी से रुपये पर दबाव रहा। हालाँकि कच्चे तेल की कीमतों में 0.7 प्रतिशत की नरमी और भारतीय पूँजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की शुद्ध लिवाली से भारतीय मुद्रा की गिरावट सीमित रही।

एनपीजी ने 97वीं बैठक में रेल और सड़क परियोजनाओं का किया मूल्यांकन

एजेंसी
नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए बुधवार को नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 97वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव पंकज कुमार ने की।वाणिज्?य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि एनपीजी की 97वीं बैठक में रेल और सड़क परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस बैठक में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स दक्षता और आर्थिक प्रभाव के लिए 5 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से तीन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की और दो रेल मंत्रालय की थीं। इनमें से दो ब्राउनफील्ड और तीन ग्रीनफील्ड परियोजनाएं हैं। मंत्रालय के मुताबिक इनमें प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन पीएम-गतिशक्ति के (पीएमजीएस एनएमपी) के मूल सिद्धांतों के अनुरूप मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स

एकीकृत मल्टीमॉडल अवसंरचना, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी और अंतर-विभागीय समन्वय के सिद्धांतों के अनुरूप होने के आधार पर किया गया। इस बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये पहल रसद दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि, यात्रा समय में कमी और जिन क्षेत्रों में ये सेवाएं प्रदान करती हैं, वहां व्यापक सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

ईडी ने मिंत्रा और संबंधित कंपनियों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये के फेमा उल्लंघन का मामला दर्ज किया

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट समर्थित 'फैशन एवं लाइफस्टाइल' प्लेटफॉर्म मिंत्रा, उससे जुड़ी कंपनियों और निदेशकों के खिलाफ 1,654 करोड़ रुपये से अधिक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उल्लंघन के लिए फेमा के तहत मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि बेंगलुर क्षेत्रीय कार्यालय ने मैसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड (मिंत्रा) और उसकी संबंधित कंपनियों एवं उनके निदेशकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 16(3) के तहत 1654,35,08,981 (1,654 करोड़ रुपये) के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की है।

ईडी ने कहा कि एजेंसी को 'विश्वसनीय जानकारी' मिली थी कि 'मिंत्रा' ब्रांड नाम वाली मिंत्रा डिजायंस प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित कंपनियां 'थोक

कैश एंड कैरी' की आड़ में बहु-ब्रांड खुदरा (एमबीआरटी) कारोबार कर रही हैं। एजेंसी ने कहा कि फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत जांच से पता चला है कि मैसर्स मिंत्रा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड ने घोषणा की थी कि वे थोक कैश एंड कैरी के कारोबार में लगे हुए हैं। इसके जरिए उन्होंने विदेशी निवेशकों से 1654,35,08,981 रुपये के बराबर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है।

लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का आईपीओ 29 जुलाई को खुलेगा, प्राइस बैंड 150-158 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी
नई दिल्ली/मुंबई। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) निवेशकों के लिए मंगलवार, 29 जुलाई को खुलेगा। कंपनी ने इसके लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 150-158 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी ने जारी एक बयान में बताया कि उसका आईपीओ 29 जुलाई को खुलेगा और 31 जुलाई को बंद होगा। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने अपने 10 रुपये अंकित मूल्य वाले इस आईपीओ के लिए मूल्?य का दायरा 150-158 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी की योजना इसके जरिए 254 करोड़ रुपये जुटाने की है। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के अनुसार निवेशक न्यूनतम 94 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 94 इक्विटी शेयरों के

गुणकों में बोली लगा सकते हैं। ये आईपीओ 18,453,575 इक्विटी शेयरों तक के नए निर्गम और प्रमोटर तथा प्रमोटर समूह के विक्रय शेयरधारकों द्वारा 5,638,620 इक्विटी शेयरों तक की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का मिश्रण है। कंपनी ने बताया कि नए शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, ताकि ऋण और सामान्य कंपनी के कामकाज के लिए भविष्य की पूंजीगत जरूरतों को पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक गैर-जमा राशि स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो भारत के ऋण बाजार में वंचित ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित है। ये ग्राहकों को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) ऋण, वाहन ऋण, निर्माण ऋण और अन्य ऋण समाधान सहित विविध उत्पाद पोर्टफोलियो प्रदान करती है। मार्च, 2025 तक इस कंपनी का परिचालन नेटवर्क राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में कुल 158 शाखाओं तक फैला हुआ है।

हरित सामग्री, स्वच्छ बिजली से कार्बन उत्सर्जन काफी घटा सकता है घरेलू वाहन उद्योगः सीईईडब्ल्यू

एजेंसी
नई दिल्ली। ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य रही राजधानी की प्रतिष्ठित संस्था काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) ने बुधवार को एक रिपोर्ट में कहा कि कम कार्बन उत्सर्जन वाले तरीकों से विनिर्मित हरित इस्पात और स्वच्छ बिजली को अपनाने पर देश में वाहन उद्योग में कार्बन उत्सर्जन का स्तर काफी हद तक कम हो सकता है।

भारत का वाहन उद्योग कारोबार के हिसाब से विश्व में तीसरे नंबर पर है। सीईईडब्ल्यू की नयी स्वतंत्र अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ बिजली और कम कार्बन उत्सर्जन वाले स्टील का इस्तेमाल करके 2050 तक अपने उत्पादन उत्सर्जन को 87 प्रतिशत तक कमी ला सकता है। 'हाउ कैन इंडियाज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गो नेट जीरो' एक्सप्लोरिंग डीकार्बोनाइजेशन पाथवेज' (भारत के वाहन विनिर्माण क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन के स्तर में शुद्ध वृद्धि शून्य कैसे हो कार्बन उत्सर्जन कम करने की राह की खोज) शीर्षक रिपोर्ट ऐसे समय आयी है जबकि भारत के कई विनिर्माताओं ने बीते दो वर्षों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का अपना उत्पादन बढ़ाया है और इसके साथ ही वे उत्सर्जन कटौती के महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इन ऑटो विनिर्माताओं ने कार्बन उत्सजन स्तर में शुद्ध वृद्धि शून्य करने की वैश्विक परिभाषाओं के अनुरूप लक्ष्य की ओर विज्ञान आधारित पहल (एसबीटीआई) के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए 2050 तक सभी विनिर्माण श्रृंखला में कार्बन उत्सर्जन कम करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रमुख वाहन विनिर्माताओं के लिए, आपूर्ति श्रृंखला स्वच्छ बनाने से न केवल उत्सर्जन घटेगा; बल्कि उनकी दीर्घकालिक लागत प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ेगी और वे पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित हो पाएंगे।

एअर इंडिया विमान में टेकऑफ के बाद आई तकनीकी खराबी, कोझिकोड से दोहा जा रहा विमान लौटा

नई दिल्ली। टाटा की अगुवाई वाली विमानन कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों में लगातार तकनीकी खराबियों के मामले सामने आ रहे हैं। केरल के कालीकट (कोझिकोड) से बुधवार को कतर की राजधानी दोहा जा रहे एयर इंडिया के विमान को उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से पायलटों और चालक दल सहित 188 लोगों को लेकर उड़ान संख्या ख्र्न्न् 375 ने सुबह लगभग 9.07 बजे कालीकट से

उड़ान भरी थी। विमान में तकनीकी खराबी आने पर पायलट ने एटीसी (हवाई यातायात नियंत्रण को जानकारी दी। दो घंटे बाद ही 11.12 बजे वापस केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। अधिकारी ने कहा कि विमान के केबिन एसी में कुछ तकनीकी समस्या थी, यह आपातकालीन लैंडिंग नहीं थी। इससे एक दिन पहले इससे पहले ही कोच्चि से आ रहा एयर इंडिया का एक विमान मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे से आगे निकल गया था, जिसके बाद विमान को जांच के लिए रोक दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि हमारी एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के बाद केरल के कालीकट लौट आई। हमने प्राथमिकता के आधार पर एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की। प्रवक्ता ने कहा इस देरी के दौरान मेहमानों को जलपान उपलब्ध कराया और फिर उड़ान रवाना हो गई।

एडीबी ने जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.50 फीसदी किया

एजेंसी
नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने व्यापार अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव को लेकर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है। एडीबी का यह अनुमान अप्रैल में लगाए गए अनुमान 6.70 फीसदी से 0.20 फीसदी कम है।एशियाई विकास बैंक ने बुधवार को जुलाई के जारी एशियाई विकास परिदृश्य (एडीओ) में भारत के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के विकास दर अनुमान को भी मामूली रूप से घटाकर 6.80 फीसदी से 6.70 फीसदी कर दिया। एडीबी के जुलाई के एशियाई विकास परिदृश्य के अनुसार यह संशोधन मुख्य रूप से अमेरिकी शुल्क और उससे जुड़ी नीतिगत अनिश्चितता के प्रभाव के कारण किया गया है। ताजा एडीओ के मुताबिक अप्रैल 2025 की तुलना में गिरावट के बावजूद भारत विश?व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। एशियाई विकास बैंक को उम्मीद है कि सेवाएं और कृषि भारत के विकास के प्रमुख चालक होंगे, तथा सामान्य से ज्यादा मानसूनी बारिश के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र को समर्थन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि आर्थिक समीक्षा में

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 6.30 फीसदी से 6.80 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को पहले के 6.70 फीसदी के स्तर से घटाकर 6.50 फीसदी कर दिया है।

चावल महँगा, गेहूँ सस्ता, तेलों में तेजी, चीनी-गुड़ नरम, दालों में घटबढ़

एजेंसी
नई दिल्ली । घरेलू जिंस बाजारों में गेहूँ में नरमी रही जबकि चावल के दाम बढ़ गये। खाद्य तेलों में भी तेजी का रुख रहा। दालों में उतार-चढ़ाव देखा गया जबकि गुड़ और चीनी के भाव टूट गये। घरेलू थोक बाजारों में चावल की औसत कीमत 17 रुपये बढ़कर 3,820.07 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुँच गयी। गेहूँ पाँच रुपये टूटकर 2,817.06 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। आटा भी करीब 11 रुपये सस्ता हुआ और 3,274.03 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।

खाद्य तेलों में तेजी रही। मूँगफली तेल औसतन 38 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ गया। सरसों तेल 61 रुपये और सोया तेल करीब 33 रुपये प्रति क्विंटल महँगा हुआ। वनस्पति के दाम में 66 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गयी। सूरजमुखी तेल करीब 67 रुपये और पाम ऑयल लगभग 68 रुपये प्रति क्विंटल चढ़ा। दाल-दलहनों में तेजी का रुख रहा। दलहन बाजार में मसूर दाल की कीमत लगभग स्थिर रही। चना दाल 24 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई। तुअर दाल का औसत भाव करीब 17 रुपये घट गया। उड़द दाल में करीब 24 रुपये प्रति क्विंटल की नरमी रही। दाल मूंग में लगभग दो रुपये की मामूली तेजी रही।

गुड़-चीनी : बाजार में गुड़ के औसत भाव करीब चार रुपये प्रति क्विंटल गिर गये। चीनी भी दो रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई है।

मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

एजेंसी
नई दिल्ली। मजबूत ग्लोबल संकेतों और वोलैटिलिटी इंडेक्स में आई गिरावट के कारण घरेलू शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई थी। बाजार खुलने के बाद पहले आधे घंटे के दौरान बिकवाली का दबाव बना रहा, लेकिन सुबह 10 बजे के पहले ही लिवालों ने अपना जोर बना दिया, जिसकी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में तेजी आ गई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.66 प्रतिशत और निफ्टी 0.63 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिन भर के कारोबार के दौरान ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में जम कर खरीदारी होती रही। इसी तरह आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, ऑयल एंड गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर रियल्टी, एफएमसीजी और कैपिटल गुड्स सेक्टर के शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज आमतौर पर मजबूती बनी रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में करीब 2 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद बढ़ कर 460.43 लाख करोड़ रुपये (अनंतिम) हो गया। जबकि पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 458.45 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 1.98 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,198 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,997 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,034 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 167 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,649 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,313 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,336 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 23 शेयर बढ़त के साथ और 7 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 38 शेयर हरे निशान में और 12 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स आज 265.06 अंक की मजबूती के साथ 82,451.87 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरुआत होने के कुछ देर बाद ही बिकवाली का दबाव बन गया, जिसकी वजह से पहले आधे घंटे के कारोबार में ही ये सूचकांक फिसल कर 82,279.73 अंक तक आ गया। इसके बाद खरीदारों ने मोर्चा संभाला और आक्रामक अंदाज में लिवाली शुरू कर दी। लगातार हो रही लिवाली के कारण आज का कारोबार खत्म होने के थोड़ी देर पहले ये सूचकांक 599.62 अंक की मजबूती के साथ 82,786.43 अंक तक पहुंच गया। हालांकि आखिरी वक्त में इंट्रा-डे सेटलमेंट की वजह से हुई बिकवाली के कारण सेंसेक्स ऊपरी स्तर से करीब 60 अंक नीचे फिसल कर 539.83 अंक की बढ़त के साथ 82,726.64 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तरह ही एनएसई के निफ्टी ने आज 78.45 अंक उछल कर 25,139.35 अंक के स्तर से कारोबार की शुरुआत की। बाजार खुलने के कुछ देर बाद ही दबाव बन जाने की वजह ये सूचकांक गिर कर 25,085.50 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद खरीदारों ने चौतरफा लिवाली शुरू कर दी, जिससे इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई।

दो दिनों की यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, स्वागत में उमड़े लोग, एफटीए पर होंगे हस्ताक्षर

एजेंसी

लंदन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को लंदन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी भरा स्वागत किया। उनके स्वागत में उत्साह से भरे लोगों की भीड़ देखी गई जिनके हाथों में तिरंगा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वागत में खड़े लोगों का आभार जताते हुए इसे दिल को छूने वाला बताया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में लंदन पहुंचे हैं, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में इसकी कई तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- यूके में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। भारत की प्रगति के प्रति उनका स्नेह और जुनून दिल को छूने वाला है। दो दिवसीय यात्रा पर लंदन पहुंचे नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में यह ब्रिटेन की चौथी यात्रा है। उनके इस दौरे में भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर होने हैं जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को एक नई ऊंचाई मिलेगी। इस यात्रा के दौरान मोदी, किंग चार्ल्स तृतीय और ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर से मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर कीर भी खासे उत्साहित हैं।

अमेरिका-जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील, ट्रंप ने दी अन्य देशों को चेतावनी

वॉशिंगटन/टोक्यो। अमेरिका और जापान के बीच अब तक की सबसे बड़ी व्यापारिक डील हुई है, जिसमें करीब 550 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा करते हुए कहा कि जापान पहली बार अमेरिका के लिए अपना बाजार पूरी तरह खोलने पर राजी हुआ है, और इस कदम से अमेरिकी व्यापार को भारी बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं टैरिफ तभी हटाऊंगा जब कोई देश अमेरिका के लिए अपने बाजार खोलने को तैयार हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो और ज्यादा टैरिफ लगाए जाएंगे। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि अब वह टैरिफ को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अन्य देश अमेरिका के साथ खुलकर व्यापार करें। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, इस डील से लाखों नई नौकरियों का सृजन होगा और इसका 90 फीसदी लाभ अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि जापान ने 15 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने पर सहमति जता दी है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलित होगा। इसी के साथ ट्रंप ने फिलीपीन्स और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापार समझौतों की घोषणा की है। इन दोनों देशों से आयातित वस्तुओं पर अब 19 फीसदी शुल्क लगाया जाएगा। यह कदम अमेरिका के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।

ईरान का बड़ा संकेतः प्रतिबंध दोबारा लगाए गए तो परमाणु संधि से बाहर हो सकता है देश

संयुक्त राष्ट्र/तेहरान। ईरान ने संकेत दिया है कि अगर यूरोपीय देशों ने उस पर दोबारा प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, तो वह परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से पारंपरिक रूप से बाहर निकलने वाला दूसरा देश बन सकता है। यह बयान ईरानी उप विदेश मंत्री और वरिष्ठ परमाणु वार्ताकार काजेम गरीबाबादी ने उस वक्त दिया जब शुक्रवार को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ होने वाली अहम बैठक से पहले राजनयिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। गरीबाबादी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, अगर स्नैपबैक प्रावधान के तहत प्रतिबंध फिर से लगाए जाते हैं, तो ईरान और संयम नहीं बरतेगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अब तक 1970 की परमाणु अप्रसार संधि का पालन किया है, जबकि देश के भीतर से इस संधि से हटने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर हालिया इजराइली और अमेरिकी हमलों के बाद। गरीबाबादी ने यूरोपीय देशों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा, अगर यूरोप की नीतियां अमेरिका के अनुरूप ही होंगी, तो हमारे लिए उनके साथ बातचीत का क्या अर्थ रह जाएगा? फिर हम सीधे अमेरिका से ही क्यों न बात करें? उन्होंने कहा कि राजनयिक प्रयास और संवाद से इस संकट को टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए यूरोप को स्वतंत्र रुख अपनाना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची और गरीबाबादी दोनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी शुक्रवार की बैठक में कोई समाधान निकल सकता है, जिससे प्रतिबंधों और संधि से बाहर निकलने की नौबत टल सके।

ईयू और अमेरिका के मध्य व्यापार विवाद गहराया, समझौते की कोशिशों के बीच जवाबी शुल्क की सूची तैयार

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने अमेरिका के साथ जारी व्यापार विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत तेज कर दी है। इसके साथ ही एक जवाबी शुल्क की सूची भी तैयार की जा रही है। यह जानकारी यूरोपीय आयोग के व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिल ने बुधवार को एक ईमेल बयान के जरिए दी। गिल ने बताया, ईयू की प्राथमिकता अब भी एक राजनयिक समाधान हासिल करने की है, जिसके लिए तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर गहन बातचीत जारी है। हालांकि, यदि वार्ता विफल रहती है, तो यूरोपीय संघ ने वैकल्पिक विकल्पों की तैयारी भी कर ली है। प्रवक्ता के अनुसार, ईयू ने पहले से मौजूद दो जवाबी सूची (लिस्ट 1 और लिस्ट 2) को मिलाकर एक संयुक्त और सुदृढ़ सूची तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसे अब सदस्य देशों की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस एकीकृत सूची में पहले से 21 अरब यूरो (लगभग 24.6 अरब अमेरिकी डॉलर) के अमेरिकी उत्पादों पर लगे शुल्क शामिल होंगे। साथ ही 72 अरब यूरो मूल्य के अतिरिक्त अमेरिकी निर्यातों को शामिल किया जाएगा।

'वोक एआई' पर ट्रंप ने लगाई पाबंदी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों में वोक (डब्ल्यूओकई) एआई के उपयोग पर रोक लगाने का एक कड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। अपने आदेश में ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ऐसे एआई से फैक्ट्स प्रभावित होते हैं। ट्रंप ने अपने आदेश में कहा, कई एआई सिस्टम्स विविधिता, समानता, समावेशन (डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन यानी डीईआई) जैसे वैचारिक एजेंडों से प्रभावित हैं, जिससे इतिहास, विज्ञान और तथ्यों की विश्वसनीयता पर आंच आती है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब से एजेंसियां केवल उन्हीं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एलएलएम) को खरीद सकेंगी जो सत्य और वैचारिक तटस्थता के दो सिद्धांतों का गंभीरता से पालन करेंगे।

इस आदेश में कई अहम बातें कही गई हैं, जैसे कि एआई को

वैचारिक रूप से तटस्थ बनाना जरूरी होगा। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, एआई मॉडल्स को सिर्फ सच्चाई और फैक्ट्स के आधार पर जवाब देने चाहिए। उन्हें किसी विचारधारा, जैसे डीईआई, को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें लिखा गया है कि एलएलएम विक्रेताओं को ये सुनिश्चित करना होगा कि मॉडल किसी एक पक्ष से प्रभावित न हो, वरना उनका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने ये भी दावा किया कि उनका देश दुनिया का उन्नत एआई ढांचा तैयार करेगा। उन्होंने कहा, ÷ मेरा प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पृथ्वी पर कहीं भी सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे उन्नत एआई बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव कर सके। वोक शब्द मूल रूप से एक सकारात्मक सामाजिक शब्द था, जिसका मतलब- सामाजिक अन्याय, नस्लवाद, लैंगिक भेदभाव, अलगाववाद जैसे मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक करना है, लेकिन हाल के वर्षों में इसका अर्थ और इस्तेमाल बदल चुका है। ये शब्द इन दिनों खुद को पोलिटिकली करेक्ट साबित करने की कोशिश के तहत किया जाता है।

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी की पार्टी सदस्यता रद्द

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) यानी नेकपा एमाले की केंद्रीय कमिटी की बैठक के निर्णय के बाद उनकी पार्टी सदस्यता रद्द की गई है। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने हाल में नेकपा एमाले की सदस्यता ली थी। इतना ही नहीं उन्होंने पिछले वर्ष और इस वर्ष पार्टी की सदस्यता का नवीकरण भी किया था, लेकिन पार्टी की केंद्रीय कमिटी की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति भंडारी को सक्रिय राजनीति में नहीं आने देने के फैसले के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि तीन दिनों तक चली केंद्रीय कमिटी की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति के सक्रिय राजनीति में आने पर प्रतिबंध लगाने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। पोखरेल ने बताया कि पार्टी की वेबसाइट में सक्रिय सदस्यता की सूची से भी उनका नाम हटा दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने काठमांडू में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सामने ही सक्रिय राजनीति में आने की घोषणा की थी।

पूर्व सीजीआई खैरुल हक ढाका में गिरफ्तार

एजेंसी

ढाका। सुबह बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एबीएम खैरुल हक को उनके धनमंडी स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा (डीबी) ने ये गिरफ्तारी की है। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार %ढाका ट्रिब्यून% के मुताबिक डीबी के संयुक्त आयुक्त मोहम्मद नसीरुल इस्लाम के अनुसार एबीएम खैरुल हक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पूछताछ के लिए उन्हें मिंटो रोड स्थित डीबी मुख्यालय ले जाया गया। फिलहाल गिरफ्तारी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। खैरुल हक ने 2010 में पदभार ग्रहण करते हुए देश के 19वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष होने पर एबीएम खैरुल हक पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हो गए। हक को साल 2013 में तीन साल के कार्यकाल के लिए लॉ कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्हें कई बार इस पद पर पुनः नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष अप्रैल के अंत में, बीएनपी समर्थक वकीलों के एक

मंच, बांग्लादेश जातीयतावादी ऐनजीबी फोरम (बीजेएएफ) ने पूर्व एबीएम खैरुल हक की गिरफ्तारी और मुकदमे की मांग की थी। बीएसएस न्यूज एजेंसी के अनुसार, उन पर देश की न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। बीजेएएफ के अध्यक्ष एडवोकेट जैनुल आबेदीन ने एक लिखित बयान में दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्यायपालिका के सीधे समर्थन से एक फासीवादी शासन स्थापित किया था। अगर न्यायपालिका ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा किया होता, तो लोकतंत्र को नष्ट नहीं किया जा सकता था। एडवोकेट जैनुल आबेदीन ने खैरुल हक को न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक शासन के पतन का मुख्य जिम्मेदार बताते हुए कहा, इतनी बड़ी तबाही के केंद्र में रहने के बावजूद, न तो उन्हें गिरफ्तार किया गया और न ही उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई। इसके बावजूद, उन्हें जवाबदेह ठहराना बांग्लादेश की जनता की एक प्रमुख मांग बनी हुई है।

ट्रंप प्रशासन को एपस्टीन केस में झटका, जज का गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से इनकार

एजेंसी

वाशिंगटन। द वाल स्ट्रीट जनरल अखबार की विशेष खबर से सुर्खियों में आए जेफरी एपस्टीन केस में ट्रंप प्रशासन को झटका लगा है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध को वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज रॉबिन रोसेनबर्ग ने ठुकरा दिया। विभाग ने अदालत से इस केस से जुड़ी ग्रैंड जूरी की प्रतिलिपियां (गोपनीय दस्तावेज) सार्वजनिक करने का आग्रह किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी न्यूज की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को इस केस से संबंधित सभी जरूरी ग्रैंड जूरी दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया था। जज रॉबिन रोसेनबर्ग ने अमेरिकी न्याय विभाग के अनुरोध पर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि एपस्टीन की जांच के सिलसिले में 2005 और 2007 के संघीय ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट जारी करने में अदालत

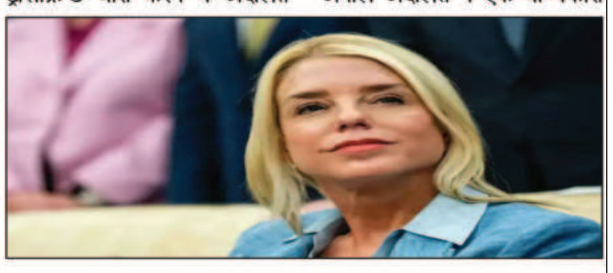

के हाथ बंधे हुए हैं। उल्लेखनीय है कि एपस्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क में मुकदमे का फैसला आने से पहले जेल में मृत्यु हो गई थी। उनकी महिला मित्र गिस्लेन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराया गया था। वह 20 साल की सजा काट रही है। रोसेनबर्ग ने फैसले में लिखा कि सरकार ने वास्तव में स्वीकार कर लिया है कि अदालत के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि 11वीं अमेरिकी सर्किट अपील अदालत ने एक बाध्यकारी मिसाल कायम की है। सनद रहे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में खुलासा किया गया है कि ट्रंप ने 2003 में एपस्टीन को उनके 50वें जन्मदिन पर एक अश्लील पत्र भेजा था। ट्रंप ने इस खुलासे के बाद द वाल स्ट्रीट जनरल के प्रकाशक, उसके दो पत्रकारों और न्यूज कॉर्प के संस्थापक रूपर्ट मर्डोक पर मुकदमा दायर किया है।

थाईलैंड की कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक, दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया

एजेंसी

बैंकॉक। थाईलैंड ने आज सुबह हवाई हमला कर कंबोडिया के दो सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच छह स्थानों पर झड़प होने की सूचना है। रॉयल थाई आर्मी के उप प्रवक्ता कर्नल रिचा सुक्सुवानन ने कंबोडिया पर हवाई हमले करने की पुष्टि की है। बैंकॉक पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार रॉयल थाई आर्मी के उप प्रवक्ता कर्नल सुक्सुवानन ने बताया कि गुरुवार सुबह उबोन रत्चथानी प्रांत से छह एफ-16 लड़ाकू विमान तैनात किए गए। इन लड़ाकू विमानों ने कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। उप प्रवक्ता के अनुसार इससे पहले कंबोडियाई सैनिकों ने पूर्वोत्तर प्रांत सुरिन में एक थाई सैन्य अड्डे पर गोलीबारी और रॉकेट दागे। उन्होंने कहा कि थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया को माकूल जवाब दिया। इस बीच, थाईलैंड का गृह मंत्रालय अपने चार प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों को एहतियात के तौर पर खाली करवा रहा है। थाईलैंड की सेना के अनुसार सुबह 7.35 बजे सूरीन के फानोम डोंग राक जिले में ता मुएन थॉम मंदिर के खंडहरों के सामने एक कंबोडियाई मानवरहित ड्रोन दिखा। इसके बाद छह कंबोडियाई सैनिक हथियारों से लैस होकर थाई सैन्य अड्डे के सामने कंटीले तारों की बाड़ के पास पहुंचे। सैनिकों ने कंबोडियाई समकक्षों से संघर्ष को और न बढ़ाने का आग्रह किया। उनके न मानने पर सुबह 8.20 बजे ता मुएन खंडहरों से लगभग 200 मीटर पूर्व में स्थित मू पा सैन्य बेस पर गोलीबारी शुरू कर दी। थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई बलों ने आसपास के इलाकों में इस तरह से तोपें तैनात की हैं कि नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद सुबह 8.50 बजे मंदिर के खंडहरों पर तोपें दागी गईं। लगभग 9.15 बजे कंबोडियाई सैनिकों ने मू पा बेस के पास के इलाके को निशाना बनाकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में एक थाई सैनिक घायल हो गया। सुबह 9.40 बजे कंबोडिया ने सी सा केत प्रांत में डॉन तुआन मंदिर के खंडहरों पर बीएम-21 रॉकेट लॉन्चर दागे। सुबह 9.55 बजे कंबोडियाई सेना ने कथित तौर पर सुरिन के कप चोएंग ज़िले में सीमा क्षेत्र विकास केंद्र के पास एक रिहायशी इलाके में गोलीबारी की। इस गोलीबारी में कम से कम तीन नागरिक घायल हो गए। यह हमले उबोन रत्चथानी प्रांत में चोंग आन मा सीमा पार के पास एक बारूदी सुरंग विस्फोट में पांच थाई सैनिकों के घायल होने के एक दिन बाद किए गए हैं। घायल थाई सैनिकों में से एक का पैर कट गया है। थाई सेना ने कहा कि ये बारूदी सुरंगें हाल ही में कंबोडिया ने बिछाई हैं। उत्तर-पूर्व के लिए जिम्मेदार द्वितीय क्षेत्र सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बूनसिन पैडक्लांग ने सीमा सील करने और सुरिन में मंदिर के खंडहरों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश गुरुवार सुबह से लागू हो गए। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने गुरुवार को फेसबुक पर कहा कि थाई सेना ने ओद्दार मीनचे प्रांत में प्रीह विहियर और ता क्रबेई मंदिरों में कंबोडियाई सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं।

रूस की अंगारा एयरलाइंस का विमान एन-24 लापता, 46 लोग हैं सवार

एजेंसी

मॉस्को। रूस की प्रमुख एयरलाइंस अंगारा का विमान एन-24 लापता हो गया है। उसमें 46 लोग सवार हैं। उड़ान भरने के कुछ देरबाद इसका संपर्क टूट गया है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के अनुसार आपातकालीन

प्रतिक्रिया सेवाओं का कहना है कि 46 लोगों को ले जा रहा एएन-24 यात्री विमान से रूस के अमूर क्षेत्र में संपर्क टूट गया है। एजेंसी तास के अनुसार अंगारा एयरलाइंस का यह विमान टिंडा हवाई अड्डे से कुछ किलोमीटर दूर एक निर्धारित चेकपॉइंट पर संपर्क करने में विफल रहा। इस विमान में दो बच्चों सहित 40 यात्री और छह चालक दल के सदस्य सवार हैं।

यूक्रेन में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय की शक्तियों में कटौती

एजेंसी

कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने देश की संसद वेरखोव्ना राडा से पारित राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एनएबीयू) और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय (एसएपीओ) की शक्तियों में कटौती करने वाले विधेयक पर बीते कल हस्ताक्षर कर दिए। यूक्रेन के लोग वेरखोव्ना राडा के विधेयक पारित करने से खफा हैं। देश में दूसरे दिन भी जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन के सूचना विभाग की समाचार एजेंसी यूक्रेनफॉर्म ने समाचार को भेजे गए आधिकारिक ई-मेल में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति के दस्तखत होने के साथ ही एनएबीयू और एसएपीओ से जुड़े इस विधेयक ने अब कानूनी शक्ल अख्तियार कर ली। इसका मकसद मार्शल लॉ के दौरान विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के लापता करने वाले कानून को संसद के आधिकारिक समाचार पत्र होलोस यूक्रेनी में अधिसूचित किया गया है।

होने पर होने वाली जांच में इन दोनों निकायों की शक्तियों और आजादी पर अंकुश लगाना है। एनएबीयू और एसएपीओ की शक्तियों को कम करने वाले कानून को संसद के आधिकारिक समाचार पत्र होलोस यूक्रेनी में अधिसूचित किया गया है। यह कानून मार्शल लॉ के दौरान विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों के लापता होने से संबंधित घटनाओं की पूर्व परीक्षण जांच की विशिष्टता के संबंध में यूक्रेन की दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों के कार्यान्वयन पर जोर देता है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अब यूक्रेन का भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा रूसी प्रभाव के बिना भी काम करेगा।

उन्होंने कहा कि एनएबीयू के निदेशक सेमेन क्रिवोनोस, एसएपीओ के अभियोजक ओलेक्सांद्र क्लिमेंको, अभियोजक जनरल रुस्लान क्रावचेंको और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के प्रमुख वासिल मालियुक से बात की है। हमने विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की। सबने माना ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं कि एनएबीयू और एसएपीओ को समाप्त कर दिया जाएगा। दोनों काम करते रहेंगे।

गाजा में भुखमरी की चेतावनी को इजराइल ने नकारा, हमास के दुष्प्रचार का हिस्सा बताया

एजेंसी

तेल अवीव। गाजा में इजराइल के रवैये से मानवीय सहायता का संकट और सामूहिक भुखमरी के विभिन्न मानवाधिकार समूहों की चेतावनी को खारिज करते हुए इजराइल ने दावा किया है कि यह हमास के दुष्प्रचार को प्रोत्साहित करने वाला हथकंडा है। इजराइल का दावा है कि गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंच रही है जो यूएन द्वारा उठाए जाने का इंतजार कर रही है। इसे इजराइल ने संकट का मुख्य कारण बताया है।

इजराइल के विदेश विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता यूएन टीम की तरफ से लिए जाने का इंतजार कर रही हैं।इजराइल का कहना है कि खाद्य सहायता लेकर 4500 ट्रक गाजा में प्रवेश कर चुके हैं, जिनमें बेकरी के लिए

इजराइल के विदेश विभाग की तरफ से दावा किया गया है कि गाजा में बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता यूएन टीम की तरफ से लिए जाने का इंतजार कर रही हैं।

आटा और 2500 टन शिशु आहार एवं बच्चों के लिए उच्च कैलोरी वाला खाद्य पदार्थ शामिल है। जबकि गाजा में 700 से ज्यादा मानवीय सहायता वाले ट्रक यूएन की तरफ से उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों और मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति में इसे बाधक बताया है। इजराइल ने उन खबरों को हमास के प्रचारतंत्र का हथकंडा बताया है जिसमें गाजा में व्यापक स्तर पर सामूहिक भुखमरी फैलने की आशंका जताई गई थी। एकदिन पहले सौ से अधिक गैर सरकारी सहायता संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने यह चेतावनी दी थी। इनका कहना था कि इजरायली हमलों और नाकाबंदी की वजह से गाजा में हालात बहुत खराब हैं और वहां व्यापक स्तर पर भुखमरी फैल रही है। इजराइल का कहना है कि युद्धविराम के लिए वार्ता के दौर में इस तरह के दावे हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहे हैं और और इस आतंकी संगठन के मंसूबों को मजबूती दे रहे हैं।

ट्रंप प्रशासन ने हत्या के दोषी अमेरिकी को वेनेजुएला की जेल से रिहा कराया

एजेंसी

वाशिंगटन। ट्रंप प्रशासन ने हत्या के दोषी एक अमेरिकी व्यक्ति को वेनेजुएला की जेल से रिहा कराया है। अदालती दस्तावेजों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह कैदियों की अदला-बदली के तहत वेनेजुएला की एक जेल से रिहा किए गए एक व्यक्ति ने तीन लोगों की हत्या की थी। इस व्यक्ति का नाम दाहुद हनीद ओर्टिज बताया गया है। उसके पास अमेरिकी और वेनेजुएला की दोहरी नागरिकता है।द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने पिछले हफ्ते वेनेजुएला की एक जेल से 10 अमेरिकियों और वैधानिक रूप अमेरिका के स्थायी निवासियों की रिहाई सुनिश्चित कराई। विदेशमंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि यह अहम कदम विदेशों में अन्यायपूर्ण तरीके से बंदी बनाए गए अमेरिकियों की भलाई की रक्षा के प्रयास का प्रतीक है। मैड्रिड स्थित अभियोजक कार्यालय के एक अधिकारी ने पहचान न उजागर करने का आग्रह करते हुए वेनेजुएला के अदालती रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि जेल से रिहा किए गए लोगों में से एक अमेरिकी-वेनेजुएला की नागरिकता प्राप्त दाहुद हनीद ओर्टिज भी है। उसे 2016 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में तीन लोगों की हत्या के लिए वेनेजुएला में दोषी ठहराया गया था। वेनेजुएला की एक अदालत ने 2023 में उसे 30 साल जेल की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तान-ईरान से निकाले गए अफगानों को तालिबान ने दी यातनाएं, मारने की धमकी भी दी

एजेंसी

वाशिंगटन। तालिबान सरकार एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के निशाने पर आ गई है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान से जबरन निकाले गए कई अफगान नागरिकों को तालिबान ने यातनाएं दीं, धमकाया और मनमाने ढंग से हिरासत में लिया। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान और ईरान लाखों अफगानों को यह कहकर देश से निकाल रहे हैं कि वे अवैध रूप से रह रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र मिशन की रिपोर्ट के मुताबिक, अफगानिस्तान लौटे कई लोग तालिबान के हाथों गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार हुए। इनमें वे लोग शामिल हैं जो पहले पश्चिम समर्थित सरकार के लिए काम कर चुके थे या ऐसे पेशे से जुड़े थे जो तालिबान की नजरों में संदेहास्पद हैं। कुछ लोगों को जान से मारने की धमकियां मिलीं, तो कई को गुमनाम रहकर जिंदगी बितानी पड़ रही है।

शारीरिक यातनाओं का दर्दनाक ब्यौरा

रिपोर्ट में एक पूर्व सरकारी अधिकारी का बयान शामिल है, जिसने बताया कि 2023 में लौटने पर उसे बुरी तरह पीटा गया, पानी में डुबोया गया और नकली फांसी

की धमकी दी गई। एक अन्य गैर-बाइनरी व्यक्ति ने कहा कि उसे बंदूक की बट से पीटा गया। ये घटनाएं दिखाती हैं कि तालिबान के दावों के उलट, लौटने वाले अफगानों के साथ सख्ती बरती जा रही है।

महिलाओं-लड़कियों की स्थिति भयावह

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा कि किसी को भी ऐसे देश में नहीं भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें उनकी पहचान या इतिहास के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़े। उन्होंने अफगान महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को विशेष रूप से चिंताजनक बताया, जिन पर तालिबान की सख्त पाबंदियां हैं। जैसे स्कूल बंद, काम करने पर रोक और सार्वजनिक जगहों पर जाने पर प्रतिबंध।

तालिबान की सफाई और यूएन से अपील

तालिबान प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि लौटने वालों को दस्तावेज, परिवहन और कानूनी सहायता दी जा रही है। साथ ही, तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वह जबरन निष्कासन को रोके और अफगान शरणार्थियों को खाना, दवा, शिक्षा और आश्रय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए।

अफगान शरणार्थियों का भविष्य संकट में

अफगानिस्तान से लाखों लोग दशकों से अलग-अलग कारणों से बाहर रह रहे थे। अब वे पाकिस्तान, ईरान या अमेरिका जैसे देशों में कानूनी सुरक्षा खो रहे हैं। अमेरिका में हाल ही में एक अदालत के फैसले से हजारों अफगानों की अस्थायी सुरक्षा समाप्त हो गई। ट्रंप प्रशासन की नीतियों और यात्रा प्रतिबंधों ने स्थिति को और खराब बना दिया है।

देश का दर्पण न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, address- 14 no V ki sikar Road